

सम-सामयिक **घटना चक्र**

अतिरिक्तांक



GS

प्वाइंटर

(पूर्वावलोकन सार)

निःशुल्क

नवंबर-दिसंबर, 2017

अंक के साथ

भारतीय

Website : <http://www.ssgcp.com/>

<https://www.facebook.com/ssgcpl>

<https://www.facebook.com/ssgc.gs.qa>

<https://plus.google.com/+Ssgcpssgcp>

<https://twitter.com/SamsamyikGhatna>

राजव्यवस्था एवं शासन

शृंखला का अगला अंक - **सामान्य भूगोल** (भारत एवं विश्व)

GS प्वाइंटर 3

भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

2017, अगस्त माह से सम-सामयिक घटना चक्र मुख्य पत्रिका के साथ निःशुल्क अतिरिक्तांक की शृंखला प्रारंभ की गई है। शृंखला में सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों पर GS 'प्वाइंटर' क्रमशः प्रस्तुत किया जाएगा।

भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

भारत का संवैधानिक विकास

- * भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई
— भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के अंतर्गत
- * कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था
— रेगुलेंटिंग एक्ट, 1773 में
- * भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी
— भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा
- * भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था — 1937 में
- * सही सुमेलित है—
नियंत्रण परिषद की स्थापना — पिट्स का भारतीय अधिनियम, 1784
- सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना — नियामक अधिनियम, 1773
- इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति — चार्टर अधिनियम, 1813
- गवर्नर-जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की निवृत्ति — चार्टर अधिनियम, 1833
- * 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं
— प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध-शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण
- * भारतीय विधानपत्रिका प्रथम बार द्वि-सदनीय बनाई गई
— 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
- * राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है—
— भारत सरकार अधिनियम, 1935 से
- * भारतावासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया
— चार्टर एक्ट, 1833 के अधिनियम ने
- * भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है — भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा
- * एक 'संघीय व्यवस्था' और 'केंद्र' में 'द्वैध शासन' भारत में लागू किया गया था—
— 1935 के अधिनियम द्वारा
- * अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था
— भारत सरकार अधिनियम, 1935 में
- * 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी
— गवर्नर जनरल को
- * भारत शासन अधिनियम, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है
— देश के लिए लिखित संविधान
- * 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है
— क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है
- * बर्मा, भारत से अलग हुआ
— गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के फलस्वरूप

- * वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था
— कुल 8 प्रांतों में
- * एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था
— द्वायस मिशन द्वारा
- * भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था
— जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना
- * कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था
— 10 लाख व्यक्ति
- * कैबिनेट मिशन के सदस्य थे
— पेथिक लार्सेन, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर
- * भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था
— कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के अंतर्गत
- * 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे—
— जवाहरलाल नेहरू
- * कथन (A): वेवेल योजना के अनुसार, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी।
कारण (R): वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता।
— कथन सही है, पर कारण गलत है।
- * भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था
— स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में
- * संविधान सभा के बारे में सही कथन हैं—
1. इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी
2. अल्पसंख्यक समुदाय जैसे- ईसाई, एंग्लो-इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।
3. इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर सम्पत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मतधिकार सीमित था।
4. वह बहुदलीय निकाय थी
- * भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
— विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया
- * संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था
— प्रांतीय सभाओं द्वारा
- * संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी
— डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने
- * भारत की 'संविधान निर्मात्री सभा' या संविधान सभा के अध्यक्ष थे
— डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- * भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी
— 9 दिसंबर, 1946 को
- * भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ
— 9 दिसंबर, 1946
- * भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था—
— 22 जनवरी, 1947 को
- * संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था
— पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा
- * भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन हैं—
1. पं. नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था।
2. उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है।
3. संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है।
- * भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे
— 12
- * भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा
— 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
- * सही सुमेलन इस प्रकार है—
संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष — एच.सी. मुखर्जी
प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र — के.एम. मुन्शी
कांग्रेसी सदस्य
राजस्थान की रियासतों का — वी.टी. कृष्णमाचारी
प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान-
सभा के सदस्य
संघ-संविधान समिति के अध्यक्ष — जवाहरलाल नेहरू
- * संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था
— सरदार पटेल
- * भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
— डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
- * संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे
— सरदार पटेल
- * डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे
— 6
- * संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया
— 29 अगस्त, 1947 को
- * भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार थे
— बी.एन. राव
- * भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था
— बी.एन. राव द्वारा

- * भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया
— 22 जुलाई, 1947 ई. को
- * संविधान निर्मात्री परिषद की 'झंडा समिति' के अध्यक्ष थे
— डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- * भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था
— 26 नवंबर, 1949 को
- * भारतीय संविधान लागू हुआ था — 26 जनवरी, 1950 को
- * संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्योंकि
— कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था
- * भारतीय संविधान को अपनाया गया था — संविधानिक सभा द्वारा
- * भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था
— 26 नवंबर, 1949 को
- * बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था—
— बंबई प्रेसीडेंसी से
- * डॉ. भीम राव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई
— क्रमशः 1891 तथा 1956 में
- * 'जन गण मन' को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया
— 1950 में
- * भारत शासन द्वारा राजकीय चिह्न (State Emblem) अंगीकृत (Adopt) किया गया था
— 26 जनवरी, 1950 से
- * सही कथन हैं—
1. तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार-विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पास्ति होने के रूप में हुई।
2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित आल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया।
- * कथन (A) : भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
कारण (R) : इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है।
— (A) और (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- * संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी
— मौलाना आज़ाद ने
- * भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया था
— महात्मा गांधी ने
- * "अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है।" यह कथन है
— आइवर जेनिंग्स का

- * "संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था"। कहा था
— ऑस्टिन ने
 - * भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्याएं थीं — 15
- ## संविधान पर विदेशी प्रभाव
- * भारत के संविधान में ज्देशिका का विचार लिया गया है
— यू.एस.ए. के संविधान से
 - * भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है — संविधान
 - * भारत में न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) की संकल्पना ली गई है
— संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
 - * भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है — कनाडा से
 - * भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में
— न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की प्रणाली है
 - * न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था — भारत और यू.एस.ए. में है
 - * भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है, वह है
— संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय
 - * भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है
— ऑस्ट्रेलिया की
 - * भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' की संकल्पना आधारित है
— आयरलैंड के संविधान पर
 - * राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे
— आइरिश गणतंत्र से
 - * सही सुमेलन इस प्रकार है—
(संवैधानिक प्रावधान) (स्रोत)

मूल अधिकार	-	सं.रा. अमेरिका
शासन की संसदीय प्रणाली	-	ग्रेट ब्रिटेन (यू.के.)
आपात उपबंध	-	जर्मनी का वीमर संविधान
राज्य नीति के निर्देशक तत्व	-	आयरलैंड

 - * सही सुमेलन इस प्रकार है :
विधि का शासन — इंग्लैंड
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया — जापान
राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना — कनाडा
विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची — ऑस्ट्रेलिया
मंत्रिमंडलीय सरकार — ब्रिटिश संविधान
केंद्र-राज्य संबंध — कनाडा का संविधान
भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है — कनाडा

- * भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है
— रूस (पूर्व सोवियत संघ) के संविधान से
- * कथन (A): भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है।
कारण (R): मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है।
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- * भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है — संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
- * लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ — अमेरिका से

संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची

- * भारतीय संविधान में हैं — 400 से अधिक आर्टिकल्स (अनुच्छेद)
- * भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे — 395
- * भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं — 12
- * सही कथन है—
— भारत के संविधान में नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों को संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया
- * भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है — बाइस भागों में
- * नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में हैं, वह है — भाग 2
- * सही सुमेलित हैं—
नागरिकता — संविधान का भाग II
मौलिक अधिकार — संविधान का भाग III
राज्य — संविधान का भाग VI
- * सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है—
सूची-I सूची-II
नए राज्यों का गठन — भारतीय संविधान का अनु. 3
नागरिकता — भारतीय संविधान का भाग-2
मौलिक अधिकार — भारतीय संविधान का भाग- 3
प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना — भारतीय संविधान का अनु. 323-A
- * हमारे संविधान का वह भाग जिसमें तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है — भाग IX
- * संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है — भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में
- * भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्योरा देती है — पहली
- * भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है — राज्य सभा में स्थानों के आवंटन को

- * यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, वह है — पहली अनुसूची
- * सही सुमेलित हैं—
(अनुसूची) (विषय)
चतुर्थ — राज्य सभा में स्थानों का आवंटन
षष्ठम — जनजातीय क्षेत्र
अष्टम — भाषा
नवम — भूमि सुधार
- * सही सुमेलित हैं—
सूची-I सूची-II
सातवीं अनुसूची — विधायी शक्तियों का वितरण
आठवीं अनुसूची — भाषाएं
नवीं अनुसूची — कुछ अधिनियमों का विधिमन्थनकरण
दसवीं अनुसूची — दल परिवर्तन के आधार पर निरहता
- * राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को, सैद्धान्तिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है — 9वीं अनुसूची में
- * भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है — समवर्ती सूची में
- * समवर्ती सूची का विषय है — आपराधिक मामले
- * भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है — जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
- * समवर्ती सूची में है — शिक्षा
- * शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया — 42वें संशोधन द्वारा
- * सही सुमेलन इस प्रकार है—
विषय सूची
वन — समवर्ती सूची
डाकघर बचत बैंक — संघीय सूची
जन स्वास्थ्य — राज्य सूची
- * सही सुमेलन इस प्रकार है
केंद्र सूची — जनगणना
राज्य सूची — पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था
समवर्ती सूची — जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
अवशिष्ट विषय (केंद्र के अधीन) — अंतरिक्ष अनुसंधान
- * भारतीय संविधान के वे प्रावधान, जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं—
1. राज्य की नीति के निदेशक तत्व, 2. ग्रामीण और शहरी, स्थानीय निकाय, 3. पंचम अनुसूची, 4. षष्ठ अनुसूची, 5. सप्तम अनुसूची

- * भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल-बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं — दसवीं अनुसूची में
- * भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है — बैंकिंग, बीमा और जनगणना का
- * वह विषय जो भारतीय संविधान की 'संघ सूची' से संबंधित हैं — रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे
- * भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है — रेलवे पुलिस का
- * 'पंचायती राज' विषय सम्मिलित है — राज्य सूची में
- * वह विषय जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II समवर्ती सूची में शामिल है — दंड प्रक्रिया
- * 'विवाह', 'विवाह विच्छेद' और 'गोद लेना' संविधान की सातवीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं — सूची III - समवर्ती सूची में
- * सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है — सातवीं अनुसूची में
- * भूमि सुधार.....के विषयों के अंतर्गत है। — राज्य सूची
- * भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है — पांचवीं अनुसूची में
- * भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वह हैं — मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम
- * भारत के संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं — अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए
- * पंचायतों को सैद्धान्तिक दर्जा प्रदान किया गया है — अनुच्छेद 243 के अंतर्गत
- * संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची संबंधित है — पंचायती राज से
- * "राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता" — यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है — अनुच्छेद 117 में
- * वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है — अनुच्छेद 117 में
- * भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है — अनुच्छेद-312 में
- * सही सुमेलित हैं—
भारत का निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324
अनुच्छेद 39A - समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता
- * सही सुमेलित है—
सूची-I
(संविधान के अनुच्छेद)
अनु. 124 -
अनु. 5 -
अनु. 352 -
अनु. 245 -
- * सही सुमेलित है—
सूची-I
अनुच्छेद 14 -
अनुच्छेद 36 -
अनुच्छेद 74 -
अनुच्छेद 368 -
- * सही सुमेलन इस प्रकार है—
सूची-I
विधानतः नए राज्य को शामिल करना -
समता का अधिकार -
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण -
राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार -
- * सही सुमेलित है—
सूची-I
(संविधान का अनुच्छेद)
अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 75
अनुच्छेद 155
अनुच्छेद 164
- * सही सुमेलित है—
सूची-I
अनुच्छेद 323-A
अनुच्छेद 324
अनुच्छेद 330
अनुच्छेद 320
वित्त आयोग
वित्तीय आपात
- सूची-II
(विषय)
संघीय न्यायपालिका
नागरिकता
आकस्मिक प्रावधान
विधायी शक्तियों का वितरण
- सूची-II
समानता का अधिकार
नीति निर्देशक तत्व
मंत्रिपरिषद
संशोधन प्रक्रिया
- सूची-II
अनुच्छेद 2
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 22
अनुच्छेद 111
- सूची-II
(अंतर्वस्तु)
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति
- सूची-II
प्रशासनिक अधिकरण
निर्वाचन
लोक सभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण
लोक सेवा आयोगों के कार्य
अनुच्छेद-280
अनुच्छेद-360

* सुमेलिता है-

सूची-I

(संस्थान)

भारत का नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक

संघ लोक सेवा आयोग

आपात स्थिति की घोषणा

सूची-II

(अनुच्छेद)

अनुच्छेद 148

अनुच्छेद 315

अनुच्छेद : 352

* सही सुमेलन इस प्रकार है-

अनु. 215—उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

अनु. 222—किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण

अनु. 226—विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति

अनु. 227—सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति

* सही सुमेलित हैं-

सूची-I

अनुच्छेद 76

अनुच्छेद 131

कार्य करने का अधिकार

कार्य करने के लिए सही

और मानवीय स्थितियां

बच्चों के लिए मुफ्त तथा

अनिवार्य शिक्षा

सूची-II

भारत का महान्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय का

क्षेत्रधिकार

अनुच्छेद 41

अनुच्छेद 42

अनुच्छेद 45

* सही सुमेलन इस प्रकार है-

भारतीय संविधान का भाग IX - पंचायत

भारतीय संविधान का भाग VIII - संघ राज्य क्षेत्र

भारतीय संविधान का भाग IVA - मूल कर्तव्य

भारतीय संविधान का भाग IXA - नगर पालिका

* सही सुमेलित है-

पंचायत - भाग 9

नगरपालिकाएं - भाग 9-क

सहकारी समितियां - भाग 9-ख

* सही सुमेलन इस प्रकार है-

संविधान का भाग XV निर्वाचन

संविधान का भाग XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

संविधान का भाग XVII राजभाषा

संविधान का भाग XVIII आपात उपबंध

उद्देशिका

* निम्नलिखित अवतरण में,

“हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को,

सामाजिक, अर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में

आज.....'X'.....को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

— 26 नवंबर, 1949

* भारतीय गणतंत्र की 26-1-1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति, जब संविधान लागू किया गया था

— संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य

* संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है-

— भारत तथा इंडिया नाम से

* भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है

— सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक

* 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं

— समाजवाद, पंथनिरपेक्षता

* भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है— संविधान की प्रस्तावना

* वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था

— अखंडता

* भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है —

एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र

* संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है-

1. पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत “ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव” अंततोगत्वा उद्देशिका बना।

2. इसकी प्रकृति न्याययोग्य (Justiciable) नहीं है।

3. संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द (Override) नहीं कर सकता।

* भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था

— बयातीसवें संशोधन द्वारा

- * वह शब्द जो 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे—
— समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता
- * भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है—
— सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा
- * 'भारत एक गणतंत्र है' इसका अर्थ है
— भारत में वंशानुगत शासन नहीं है
- * भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है
— हम भारत के लोग शब्दों से
- * 'हम, भारत के लोग (We the People of India)' शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया
— संविधान की प्रस्तावना में
- * "सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं"। यह सिद्धांत जाना जाता है
— सार्वभौमिकता
- * भारत के संदर्भ में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का सही भाव व्यक्त करता है
— भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
- * भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है
— लोक कल्याण
- * भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है
— आर्थिक स्वतंत्रता का
- * भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है
— धार्मिक न्याय
- * संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है
— "समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष" शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे
- * संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है
— उद्देशिका
- * भारतीय संविधान की प्रस्तावना को "हमारे संप्रभु, प्रजातंत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली" कहा
— के.एम. मुंशी ने
- * संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है
— बी.आर. अम्बेडकर ने
- * उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि 'उद्देशिका संविधान का भाग है'
— बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में
- * सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया
— केशवानंद भारती विवाद में
- * भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का उपबंध किया गया है
— उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में
- * भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है
— मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में

- * भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है
— संविधान की प्रस्तावना
- * भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है
— तीन प्रकार के न्याय की

शासन प्रणाली

- * राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है
— संप्रभुता
- * भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, वह है
— संसदात्मक
- * भारतीय संविधान की विशेषता है
— संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका
- * भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि
— मंत्रिपरिषद, लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है
- * भारत के संदर्भ में, संसदीय शासन-प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं :
1. मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं।
2. जब तक मंत्रियों को संसद (लोकसभा) का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं।
- * संसदात्मक शासन व्यवस्था में
— विधायिका का कार्यपालिका पर निबंधन होता है।
- * राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं
— राष्ट्रपति में
- * भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं—
1. यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है।
2. इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है।
3. सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।
- * सही कथन हैं—
1. भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है।
2. भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है।
3. भारत में लोकतांत्रिक समाज है।
4. भारत एक कल्याणकारी राज्य है।
- * भारतीय राजतंत्र की विशेषता है—
— एक संघीय संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन
- * 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) का उद्देश्य है
— अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना
- * भारतीय संविधान का दर्शन है
— कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता
- * भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है
— जनता
- * अक्षय्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है
— एकल कार्यपालिका

- * भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि
— जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है
- * भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है
— केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से
- * भारतीय संविधान है — अंशतः कठोर और अंशतः लचीला
- * भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है — वार्षिक समीक्षा का
- * कथन (A) : भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है।
कारण (R) : उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है।
— दोनों (A) और (R) सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- * भारत के संविधान का संघीय लक्षण है
— केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका
- * भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं
— राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं
- * भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है
— संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है।
- * कथन (A) : भारत का राष्ट्रपति परेक्षितः निर्वाचित होता है।
कारण (R) : भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है।
— दोनों (A) और (R) सत्य हैं तथा (R), (A) का एक मान्य स्पष्टीकरण है।
- * कथन (A) : राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन-रक्त हैं।
कारण (R) : लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं।
— (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) सही स्पष्टीकरण है (A) का।
- * कथन (A) : भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है।
कारण (R) : भारत एक संघीय राज्य नहीं है।
— A सही है, परंतु R गलत है।
- * कथन (A) : भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहु-आयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था।
कारण (R) : विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, न कि कमजोर, भारतीय राष्ट्रियता का निर्माण हुआ है।
— (A) और (R) दोनों अपने आप में सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

- * कथन (A) : महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं।
कारण (R) : भारत में लोकतंत्र अधिक आत्म-सम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। — दोनों (A) और (R) सत्य हैं तथा (R), (A) का एक मान्य स्पष्टीकरण है।
- * भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं
— यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है।
- * कारण (A) : भारतीय संविधान अर्द्ध संघात्मक है।
कारण (R) : भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक।
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- * भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है — जी. आस्टिन ने
- * "भारत अर्द्ध संघात्मक राज्य है", कहा था — के.सी. व्हीयर ने
- * "भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।" कथन है — के.सी. व्हीयर का
- * "संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है", कथन है — बी. आर. अम्बेडकर का
- * भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही है—
— धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति
- * गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है
— एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो
- * संवैधानिक सरकार वह है — जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।

राष्ट्रीय प्रतीक

- * भारत का राष्ट्रीय पशु है — बाघ
- * भारत का राष्ट्रीय पुष्प है — कमल
- * भारत का राष्ट्रीय पक्षी है — मोर
- * 'भारतीय राष्ट्रीय ध्वज' में चक्र प्रतीक है — न्याय का
- * भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों (तीली) की कुल संख्या है — 24
- * संपूर्ण राष्ट्र गान का वादन (गायन) काल है — 52 सेकंड

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र

- * भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है
— संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत
- * नए राज्य के गठन (carve out) की शक्ति निहित है — संसद में
- * भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है — संसद को

- * एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकायी शक्ति प्राप्त है — संसद को
- * संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है — राज्यों का यूनियन (संघ)
- * नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है — संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक इसे उस राज्य के विधान मंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है।
- * भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है — संसद में साधारण बहुमत द्वारा।
- * भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है — राष्ट्रपति द्वारा
- * कथन (A) : भारत संघ नहीं है
कारण (R) : किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है।
— A गलत है, किंतु R सही है।
- * नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है—
— किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर
- * सही कथन हैं—
1. संविधान में "यूनियन ऑफ स्टेट्स" शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।
2. एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी।
3. पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पद्मिनी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी, राज्यों के पुनर्गठन में भाषायी आधार के पक्ष में नहीं थी।
- * यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, तो संशोधन करना आवश्यक होगा — प्रथम अनुसूची को
- * भारत में संघ शासित प्रदेश हैं — 7
- * लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटें (स्थान) आरक्षित हैं — 20
- * राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर, 1956 को बनाए — 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य।
- * भारत में — 29 राज्य एवं 7 संघशासित प्रदेश हैं
- * संघ राज्य क्षेत्र हैं — अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दीव तथा पुडुचेरी
- * वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया — आंध्र प्रदेश (नई राजधानी के रूप में हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित)
- * दिल्ली है — एक केंद्रशासित प्रदेश
- * दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया — 69वें संविधान संशोधन द्वारा
- * सही कथन हैं—
(i) गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
(ii) दीव, खम्भात की खाड़ी (Gulf of Khambhat) में एक टापू है
(iii) दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया
- * सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया — 36वें संविधान संशोधन द्वारा
- * राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है — नगालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
- * भारतीय राज्यों का, उनके निर्माण के अनुसार, कालानुक्रम है — 1. सिक्किम, 2. अरुणाचल प्रदेश, 3. छत्तीसगढ़, 4. झारखंड
- * छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया — 1 नवंबर, 2000 को
- * उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई — वर्ष 2000 में
- * विकल्प में दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्षों में हुआ था—
राज्य गठन का वर्ष
आंध्र प्रदेश - 1953
हरियाणा - 1966
हिमाचल प्रदेश - 1971
सिक्किम - 1975
- * सही सुमेसन है—
राज्य स्थापना वर्ष
नगालैंड - 1 दिसंबर, 1963
मेघालय - 21 जनवरी, 1972
सिक्किम - 16 मई, 1975
अरुणाचल प्रदेश - 20 फरवरी, 1987
- * राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है—
राज्य निर्माण का वर्ष
हरियाणा - 1966
महाराष्ट्र - 1960
राजस्थान - 1956
- * सत्य कथन हैं—
— गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया।
बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया।
हिमाचल प्रदेश पहले संघशासित प्रदेश की सूची में था।

- * 'उल्फा' उग्रवादी संबंधित है — असम से
- * 'पीपुल्स वार ग्रुप' नामक आतंकवादी संगठन स्थित है — आंध्र प्रदेश में
- * कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं — कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल
- * भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी — 29 दिसंबर, 1953 को
- * भाषायी आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ है — आंध्र प्रदेश का
- * आंध्र प्रदेश एक भाषायी राज्य के रूप में गठित किया गया — 1953 में

नागरिकता

- * भारतीय संविधान प्रदान करता है — एकल नागरिकता
- * भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है—
— जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भू-भाग के सम्मिलन द्वारा
- * नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्डधारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं — एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता/परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह/पितामही, मातामह/मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे।
- * सही कथन है — नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I तक अंतर्विष्ट किए गए।
- * दोहरी नागरिकता (Policy of Dual Citizenship) का सिद्धंत स्वीकार किया गया है — संयुक्त राज्य अमेरिका में
- * नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है — संसद

मूल अधिकार

- * सही कथन है — भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था।
- * संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है — सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को

- * 'मौलिक अधिकार' हैं — वाद योग्य
- * मौलिक अधिकार — आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं
- * भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं — अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है — अनुच्छेद 14
- * 'समानता का अधिकार' संविधान के निम्न अनुच्छेदों में के अंतर्गत दिया हुआ है— अनु. 14, अनु. 15, अनु. 16, अनु. 17 एवं अनु. 18
- * शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर-सरकारी व गैर-अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है— अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत
- * कथन (A) : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है।
कारण (R) : समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी।
— (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
- * संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद/राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों/कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है — अनुच्छेद 13
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है — मौलिक अधिकार के संदर्भ में
- * भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता का अधिकार' चार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं — अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक
- * भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया (a) संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त 'समाजवादी' शब्द (b) (a) को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना (c) (a) को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना
- * धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (भारत के संविधान का अनुच्छेद 15) एक मूल अधिकार है, जिसे वर्गीकृत किया जाएगा — समता का अधिकार के अधीन
- * भारतीय संविधान में, समता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं — अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18
- * भारतीय संविधान में जैसा निहित है, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है — कानून के साथ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता

- * मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है — अनुच्छेद 24
- * आई.सी.सी.पी.आर. के अनुच्छेद _____ द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। — 24
- * अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है — अनुच्छेद - 17 द्वारा
- * न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य 'अस्पृश्यता' के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध _____ के संबंध में किया गया है। — अनुसूचित जाति के सदस्य
- * भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है — 1. कानून बनाकर, 2. शिक्षा की उन्नति द्वारा, 3. जनजागरण के द्वारा
- * 'मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन' 1951 के मुकद्दमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, वह है — भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
- * अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया — अनुच्छेद 17 के अंतर्गत
- * भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है — अनुच्छेद 19(1) अ में
- * भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है — अनुच्छेद 19 में
- * स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में "बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता" के अंतर्गत नहीं आता है — घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते
- * नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है — अवांछनीय आलोचना के कारण
- * व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है — अनुच्छेद 21
- * अनुच्छेद 19(1) d को अनुच्छेद 21 से गिराकर पढ़ने पर प्राप्त होता है — एकांतता का अधिकार
- * धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं— (I) धर्म प्रचार करने का अधिकार (II) सिक्खों को 'कृपाण' धारण करने एवं रखने का अधिकार (III) राज्यों को समाज-सुधारक विधि निर्माण का अधिकार
- * संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, धर्म-स्वातंत्र्य का अधिकार अधीन है — सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के
- * सिक्खों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है — अनुच्छेद 25 के अंतर्गत
- * अनुच्छेद 25 का संबंध है — धर्म की स्वतंत्रता से
- * सही सुमेलित है— अ व अनुच्छेद 23 - मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कृत का प्रतिबंध अनुच्छेद 24 - कारखानों आदि में बातकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- * सही सुमेलित है— मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्कृत का प्रतिषेध - अनुच्छेद 23 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण - अनुच्छेद 29 संवैधानिक उपचारों का अधिकार - अनुच्छेद 32
- * अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है — अनुच्छेद 30
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं — मौलिक अधिकार
- * सही सुमेलन इस प्रकार है— सूची-I (भारतीय संविधान का अनुच्छेद) सूची-II (प्रावधान)
- A. अनुच्छेद 16(2) - किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- B. अनुच्छेद 29(2) - किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
- C. अनुच्छेद 30(1) - सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा।
- D. अनुच्छेद 31(1) - किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाए उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
- * मौलिक अधिकारों का संरक्षक है — न्यायपालिका

* सही कथन हैं—

- (i) के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे
- (ii) संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया
- (ii) बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई।
- * नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है — उच्चतम न्यायालय को
- * डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है — संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- * कथन (A): संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था।
- कारण (R): अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है।
- (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
- * व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है — हैबियस कार्पस (बंदी-प्रत्यक्षीकरण) को
- * सही सुमेलन इस प्रकार है—
- मौलिक कर्तव्य - संविधान का 42वां संशोधन
- संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है - केशवानंद भारती केस
- इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध - संविधान का अनुच्छेद 23
- * सही सुमेलन इस प्रकार है—
- | सूची-I | सूची-II |
|--|----------------|
| उपाधियों का निषेध | — अनुच्छेद 18 |
| धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता | — अनुच्छेद 26 |
| अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण | — अनुच्छेद 29 |
| शिक्षा का अधिकार | — अनुच्छेद 21A |
- * संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया — केशवानंद भारती बाद ने
- * भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत (बुनियादी ढांचा सिद्धांत) का प्रतिपादन किया है — केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में
- * संपत्ति का अधिकार है — कानूनी अधिकार
- * संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया — संविधान (चौवालीसवां संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा
- * वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक — वैधानिक/विधिक/कानूनी अधिकार

- * भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है — समान आवास का अधिकार
- * भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं — अनुच्छेद 14-18
- * भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है — सूचना का अधिकार
- * सभी व्यक्तियों को प्राप्त है — विधि के समान संरक्षण का अधिकार
- * भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता — व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का
- * सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है — (1) आवास के अधिकार तथा (2) विदेश यात्रा के अधिकार को
- * किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि
1. इससे वाक स्वतंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा
 2. इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा
 3. राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाता कोई विधिक उपबंध नहीं है
- * विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है — अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
- * भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं (i) भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (ii) देशभर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता (iii) चुनाव लड़ने का अधिकार
- * भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार, जो गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध है — संवैधानिक निराकरण का अधिकार
- * भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त 'समाजवाद' शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई, वे हैं — अनुच्छेद 14 तथा 16
- * लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है— अनुच्छेद 16(1) और 16(2)
- * भारतीय संविधान मान्यता देता है — धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को
- * छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों (शिशुओं) को शिक्षा का अधिकार — मूल अधिकार है
- * भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ गया — 1 अप्रैल, 2010 को

- * **कथन (A)** : राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
- कारण (R)** : एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है।
- (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
- * वह अधिकार जो, राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है— व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त 'हिंदू' शब्द सम्मिलित नहीं करता — **भारतियों को**
- * भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, तो वह निम्न विशेष लाभ/लाभों का हकदार हो जाता है
 - यह संप्रदाय/समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है।
- यह संप्रदाय/समुदाय प्रधानमंत्री के 15 घाइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है।
- * किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह प्रावधान है
 - अनुच्छेद 20 (3) में
- * दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व-अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है
 - अनुच्छेद 20
- * विधि की सम्यक् प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है
 - अनुच्छेद 21 में
- * बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है
 - अनु.22 से
- * प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है
 - 3 माह के लिए
- * वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है
 - बंदी प्रत्यक्षीकरण
- * बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम संसद ने पारित किया था
 - 1976 में
- * जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है-
 - (a) भारत के संविधान द्वारा
 - (b) 10 दिसंबर, 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा
 - (c) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा
- * पूर्ति कीजिए :
 - '_____ बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है, जैसे मनुष्य बिना परछाई के।' — अधिकार

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

- * राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है-
 - सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना
- * राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य है—
 - एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक-आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना
- * राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में सही कथन हैं—
 1. ये तत्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
 2. इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (एनफोर्सिबल) नहीं हैं।
- * कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है-
 - राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में
- * भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति-निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई
 - आयरलैंड संविधान से
- * नीति-निदेशक सिद्धांत
 - बाद योग्य नहीं है
- * भारत के संविधान के अनुसार, देश के शासन के लिए आधारभूत है
 - राज्य की नीति के निदेशक तत्व
- * समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक
 - राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों का अंग है
- * भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है
 - राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत
- * राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है
 - अनुच्छेद 40
- * भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन-
 - निदेशक सिद्धांत है।
- * सही सुमेलन इस प्रकार है—
 - अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का गठन
 - अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
 - अनुच्छेद 44 : नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
 - अनुच्छेद 48 : कृषि एवं पशुपालन का गठन
- * कथन (A) : मनरेगा दर अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है।
 - कारण (R) : रोजगार का अधिकार संविधान के भाग III में प्राविष्ट है।
 - (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

- * राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है—
अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है।
अनुच्छेद 41 : काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद 43 (क) : उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार
अनुच्छेद 48 (क) : पर्यावरण संरक्षण
 - * भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है — राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में
 - * भारत की विदेश नीति से संबंधित है — अनुच्छेद 51
 - * संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियां
 - * राज्य के नीति-निदेशक तत्व हैं—
(a) मद्यनिषेध, (b) गौ-संरक्षण, (c) पर्यावरण-संरक्षण
 - * राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है — क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं
 - * गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं — ग्राम पंचायतों को संघटित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
 - * राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है — प्रौढ़ शिक्षा
 - * राज्य का नीति-निदेशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया — मुफ्त कानूनी सलाह
 - * राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है — सूचना का अधिकार
 - * नीति-निदेशक तत्व है — समान नागरिक संहिता
 - * राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में है—
— राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं की समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, — काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहें
 - * 'राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।' कहा था — के.टी. शाह ने
- ## मूल कर्तव्य
- * भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को रखा गया है — तीसरे स्थान पर
 - * भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 'मूल कर्तव्यों' को सम्मिलित किया गया है — अनुच्छेद 51A में
 - * भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया — स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर
 - * संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया — 1976 में
 - * भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं — भाग IVA (4 क) में
 - * भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए — 42वें संविधान संशोधन द्वारा
 - * भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं — अनुच्छेद 51-क में
 - * मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है — उन्हें सैधनिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना सैधनिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है
 - * भारत में मौलिक कर्तव्य है — हमारी भिन्नी-जुती संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना
 - * एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है—
— प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें
 - * भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है — देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना।
 - * भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं — मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। वैज्ञानिक मनेदशा और खोज की भावना का विकास। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न।
 - * भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है — वन्य प्राणी का संरक्षण
 - * "भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार"। शामिल है — अनुच्छेद 51-क में
 - * सही कथन हैं — मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग-IV क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51-A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है।
 - * भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं — ग्यारह
 - * भारतीय संविधान के भाग IVA (मूल कर्तव्य) में वर्णित है — राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। भारत के सभी लोगों के मध्य भाई-चारे का भाव विकसित करना। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना।

- * सही सुमेलित है—

संविधान का भाग	विषय
(a) भाग II	नागरिकता
(b) भाग III	मूल अधिकार
(c) भाग IV	राज्य की नीति के निदेशक तत्व

- * "भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।" यह उपबंध किया गया है — मूल कर्तव्य में

राष्ट्रपति

- * कथन (A): संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है।

कारण (R): राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है।

— (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

- * भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है — अप्रत्यक्ष मतदान से

- * कथन (A): भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है।

कारण (R): एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है।

- (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।

- * भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है

— एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा

- * राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं

— संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,

सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

- * राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है

- निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है।

- * भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम — पचास निर्वाचकों द्वारा

- * राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि

— वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो

- * भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या, उस राज्य की जनसंख्या को विधान सभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की एक हजार के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में "जनसंख्या" से तात्पर्य यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है

— 1971 की जनगणना द्वारा

- * राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है

— आयु 35 वर्ष है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो

- * एक सांसद अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु

— निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी।

- * राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है — अनुच्छेद 57

- * अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है — भारत के सर्वोच्च न्यायालय को

- * राष्ट्रपति पांच वर्ष तक अपने पद पर रहता है—

— अपने पद ग्रहण के दिन से

- * भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है

— भारत के उपराष्ट्रपति को

- * भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है

— संसद द्वारा

- * राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है— अनुच्छेद 61 के द्वारा

- * राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है

— संसद के किसी भी सदन द्वारा

- * भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है

— कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना

- * भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है

— राज्यों की विधान सभाएं

- * भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है

— अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया

- * पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए

— रिक्ति होने की तिथि से छह माह के भीतर

- * जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है — 6 माह तक

- * यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा

— सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

- * भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष (Executive Head) है

— राष्ट्रपति

- * संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं

— अनुच्छेद 53 के अंतर्गत

- * **कथन (A):** संघ की कार्यपालिका शक्तियां मास्त के राष्ट्रपति में निहित हैं
- * **कारण (R):** कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं।
 - (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है (A) का।
- * सही कथन हैं
 - प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो।
- * भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है — भारत का राष्ट्रपति
- * राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है— 44 वें संशोधन द्वारा
- * राष्ट्रपति लोक सभा को बंग कर सकते हैं
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति पर
- * अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है— — राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है—
 - वह संसद का एक संघटक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है।
- * भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, वह था—
 - भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक
- * एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था, जिसे संविधानिक शब्दावली में 'जेबी निषेधाधिकार' कहा जाता है, वह थे
 - ज्ञानी जैल सिंह
- * राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं — अनुच्छेद 111 के अंतर्गत
- * जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है
 - राष्ट्रपति को
- * राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है
 - विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोककर रखना तथा संसद को संदेश भेजना
- * राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है
 - विधेयकों पर स्वीकृति देना
- * जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (वर्ष 2002 में) चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी
 - अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
- * भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है
 - अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
- * राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है
 - 6 सप्ताह तक
- * भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है
 - वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री
- * राष्ट्रपति नियुक्ति करता है—
 - भारत का महासूचनावादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल
- * भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है—
 - प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- * संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है
 - अनुच्छेद 160 में
- * भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है
 - राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का
- * राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है
 - अनुच्छेद 143
- * भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है — राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए
- * संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति की 'शक्ति' नहीं है
 - संसद के सदनों को संदेश भेजना
- * भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, कि वह
 - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए
- * राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक
 - न्यायिक शक्ति है
- * भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार हैं
 - औपचारिक (स्टिट्यूलर) और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र
- * भारतीय संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं
 - संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को
- * वह संवैधानिक विशेषाधिकार, जो राष्ट्रपति का नहीं है
 - वितीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना
- * संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल
- * **कथन (A):** भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से निम्न है।
- * **कारण (R):** भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है
 - A सही है, परंतु R गलत है।

- * कथन (A) : राष्ट्रपति संसद का भाग है।
कारण (R) : संसद के दोनों सदनों द्वारा पास्ति विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है।
- (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- * कथन (A) : रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है।
कारण (R) : प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है।
- (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- * स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे - बिहार से
- * भारत के चौथे राष्ट्रपति - श्री वी.वी. गिरि थे
- * दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- * भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है - नीलम संजीव रेड्डी
- * सूची-I का सूची-II से सुमेलन निम्नवत है-

सूची-I (राष्ट्रपति)	सूची-II (अवधि)
फखरुद्दीन अली अहमद	1974-1977
एन. संजीव रेड्डी	1977-1982
डॉ. ज़ाकिर हुसैन	1967-1969
वी.वी. गिरि	1969-1974
- * राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे - नीलम संजीव रेड्डी
- * भारत के राष्ट्रपतियों में 'दार्शनिक-राजा' अथवा 'दार्शनिक-शासक' के रूप में जाना जाता है - डॉ. राधाकृष्णन
- * भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है - वी.वी. गिरि
- * भारत के राष्ट्रपति को 'मिसाइल मैन' की संज्ञा दी जाती है - डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को
- * भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह - जस्टिस एम. हिदायतुल्ला
- * कथन सत्य है-
- राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम-से-कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति बनता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे
- * कथन : अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
कारण : राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है।
- कथन सही है, परंतु कारण गलत है।
- * श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था - 12वां
- * एक विधेयक, जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है - जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है

- * किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है - राष्ट्रपति को
- * "वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है" यह उक्ति लागू होती है - राष्ट्रपति
- * भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका था - डॉ. जाकिर हुसैन (वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी)
- * राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था-
- एडविन ल्यूटियनस द्वारा

उपराष्ट्रपति

- * भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं - संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
- * कथन (A) : कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है।
कारण (R) : उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपर्युक्त बक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर सही है - दोनों (A) और (R) सत्य हैं तथा (R), (A) का एक मान्य स्पष्टीकरण है।
- * उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन हैं -
- किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का।
- * भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है - लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से
- * भारत का उपराष्ट्रपति
 1. भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है।
 2. के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य (दायित्व) नहीं है।
 3. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है।
 4. राष्ट्रपति की पद-त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
- * उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है - राज्य परिषद (राज्य सभा) के प्रस्ताव के द्वारा
- * उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है - राज्यसभा में
- * राज्यसभा का सभापति है - उपराष्ट्रपति
- * एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है, जो उसका सदस्य नहीं होता है - राज्यसभा
- * दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे - डॉ. एस. राधाकृष्णन और वी.वी. गिरि
- * मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक - 12वां

केंद्रीय मंत्रिपरिषद

- * भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है
— प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है।
- * भारत का प्रधानमंत्री _____ होता है — नियुक्त
- * सत्य कथन है—
(a) राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है।
(b) कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता।
(c) एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए दो मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी।
- * भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है— — केंद्रीय सरकार का
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का—
— प्रधानमंत्री के
- * कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं — केवल कैबिनेट मंत्री
- * संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है
— प्रधानमंत्री के पास
- * सही कथन है
— राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
- * यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो
— वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे
- * भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है — अनुच्छेद 75
- * आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है — लोक सभा का सदस्य
- * "कौन्सिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च" का अध्यक्ष है
— भारत का प्रधानमंत्री
- * राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है — प्रधानमंत्री
- * भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय
— जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे छः माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए।
- * भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए
— 25 वर्ष
- * उपप्रधानमंत्री पद का सृजन
— संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ।
- * प्रधानमंत्री को — राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है
- * भारत का प्रधानमंत्री—
— अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है
- * जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है—
— छह माह तक
- * भारत की संसद के संबंध में कथन सही है
— संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है, मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए
- * मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है
1. लोकसभा के प्रति
2. एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत
3. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार
- * केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है
— राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक, उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी।
- * सही कथन हैं
संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। विधि-निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेगा।
- * भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है
— प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे, तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए
- * भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है — विश्वास प्रस्ताव
- * बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा — लोकसभा के सदस्यों द्वारा
- * अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है — स्पीकर की
- * लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 'अविश्वास' का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है — 50
- * भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है—
1. भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- * लाभ के पद का निर्णय (Decision) करेगा — संघीय संसद

- * भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका.....के अधीन रहकर कार्य करती है। — विधायिका
- * उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में खास मंत्री बना? — कैलाश नाथ काटजू
- * स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे — स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के.पणमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर, 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था।
- * भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री था — वी.आर. अम्बेडकर
- * भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है — बजट शब्द
- * भारत के 12 वें प्रधानमंत्री थे — देवेगौड़ा
- * सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है—
(i) विश्वनाथ प्रताप सिंह —2 दिसंबर, 1989–10 नवंबर, 1990
(ii) चंद्रशेखर - 10 नवंबर, 1990 – 21 जून, 1991
(iii) एच.डी देवेगौड़ा - 1 जून, 1996– 21 अप्रैल, 1997
(iv) इंद्र कुमार गुजराल—21 अप्रैल, 1997–18 मार्च, 1998
(v) अटल बिहारी वाजपेयी— 19 मार्च, 1998–22 मई, 2004
- * नोट- उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार है— 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक, 19 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक तथा 13 अक्टूबर, 1999 से 22 मई 2004 तक।
- * एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं—
— जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह
- * भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई — ताल बहादुर शास्त्री की
- * भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे — चंद्रशेखर
- * भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ — चौधरी चरण सिंह
- * संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह— — अनुच्छेद 352 में
- * भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं—
1. वी. पी. सिंह 2. आर. वेंकटरमण
3. वाई. बी. चव्हाण 4. प्रणव मुखर्जी
- * उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री — नरसिम्हा राव द्वारा
- * मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है—
— भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि
- * कथन : (1) मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं।
कारण : (2) संसदीय प्रणाली में 'मंत्रियों का उत्तरदायित्व' का सिद्धांत कार्य करता है।
— कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- * कथन (A) : भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के प्रति उत्तरदायी है।
कारण (R) : लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं।
— कथन गलत है, पर कारण सही है।
- * कथन (A) : किसी व्यक्ति को उपप्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है।
कारण (R) : वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- * संविधान संशोधनों में से एक, बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या, प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी — 91वां
- * केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है
— 15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
- * अधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है — श्वेत पत्र
- * प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े — अनुच्छेद 257
- * संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था
— गोपालस्वामी आयंगर रिपोर्ट पर
- * मंत्रिमंडल सचिवालय का/के कार्य है/हैं
1. मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना
2. मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता
- * सही सुमेलन है—
(a) जे. एल. नेहरू — शांति वन
(b) एल. बी. शास्त्री — विजय घाट
(c) इंदिरा गांधी — शक्ति स्थल
- * 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया — ताल बहादुर शास्त्री

महान्यायवादी और सी. ए. जी.

- * भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है
— अटॉर्नी जनरल
- * राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है
— भारत का महान्यायवादी
- * भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है — राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है
— महान्यायवादी
- * अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा
— महान्यायवादी को
- * भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के विषय में सही है—
(1) वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
(2) उसमें वही योग्यताएं हनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं
- * संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है
— भारत के अटॉर्नी जनरल को
- * भारत का महान्यायवादी
(1) लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है
(2) लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है।
(3) लोकसभा में बोल सकता है
- * सॉलिसिटर जनरल होता है
— कानूनी/न्यायिक सलाहकार
- * कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है?
— एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता)
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है—
— राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है
— अनुच्छेद 148 के अंतर्गत
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है
— भारत के राष्ट्रपति को
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था
— संविधान द्वारा
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है
— 6 वर्ष
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है—
(a) उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
(b) उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है।
(c) सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं।
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है—
(a) भारत की संवित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
(b) आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
(c) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखापरीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
- * लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व है—
(i) CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार-विमर्श करती है; (ii) CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं, जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है।
- * नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है—
— संसद की
- * संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है
— भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक
- * नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है
— संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर
- * भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है
— लोक लेखा समिति का
- * 1971 का संशोधन (महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति) अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सी.ए.जी. को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया
— 1976 में
- * लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है
— नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को
- * लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रिया-कलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं—
(a) सार्वजनिक खर्च का परीक्षण
(b) सार्वजनिक राजस्व
(c) वित्तीय प्रशासन

वरीयता अनुक्रम

- * अग्रता-क्रम में इनका सही अनुक्रम है-
 - भारत में मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव
- * भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है — भूतपूर्व राष्ट्रपति
- * भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है — भारत के मंत्रिमंडल सचिव

संसद (1)

- * लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है - — 25 वर्ष
 - * 84 वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या, 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी, जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है — 2026
 - * भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है — 552
 - * लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी — 31वें संशोधन ने
 - * भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, लोक सभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन.....जनगणना के आधार पर है। — 1971
 - * लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है — जनसंख्या आधार पर
 - * इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण नहीं है—
 - अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय
 - * इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है— — केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक
 - * यदि किसी राज्य के लिए लोक सभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी—
- नोट : अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वहीं होगा, जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात

उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोक सभा सदस्यों की संख्या 42 थी जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थीं। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 हैं।

- * लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं — मध्य प्रदेश में
- * लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है — भारत के राष्ट्रपति के पास
- * राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है — अनुच्छेद 333 के द्वारा
- * राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय से नामित कर सकता है, यदि वह इस राय का है कि लोक सभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है — 2 सदस्यों को
- * राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं — 7 वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन
- * लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है — प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
- * लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं — वर्ष में दो बार
- * लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है — कुल सदस्य संख्या का 1/10
- * लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह है— — 550
- * लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है — 545
- * संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है — संसद के दोनों सदनों में
- * लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है — स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा
- * लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है— राष्ट्रपति
- * लोकसभा का कार्यकाल — आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है
- * लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है — उत्तर प्रदेश
- * जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, लोक सभा में प्रथम स्थान-उत्तर प्रदेश - 80 सीटें
- द्वितीय स्थान-महाराष्ट्र - 48 सीटें
- तृतीय स्थान- प. बंगाल - 42 सीटें
- * लोकसभा के स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है — 25

* सही सुमेलित हैं—

राज्य	प्रतिनिधित्व
(i) आंध्र प्रदेश	— 25
(ii) तमिलनाडु	— 39
(iii) महाराष्ट्र	— 48
(iv) छत्तीसगढ़	— 11
(v) पश्चिम बंगाल	— 42

नोट-ज्ञातव्य है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था, तब वहां कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 तथा तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं।

- * लोकसभा के दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं — त्रिपुरा से
- * राज्यों/संघशासित क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल एक सीट है—
— बंझीगढ़, सिक्किम, विजोरम
- * डिजिटल मिशन के बाद यू.पी. में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है — उन्नाव
- * वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है — 70 लाख रु.
- * लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था — 1952 में
- * नवीं लोकसभा भंग की गई — 13 मार्च, 1991 को
- * भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए— फरवरी, 1998 को
- * कथन (A) : रा.ज.ग. सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद-विवाद (discussion) पसंद नहीं करती है।
कारण (R) : इस नियम में वाद-विवाद के साथ-साथ मतदान का भी प्रावधान है।
— A तथा R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
- * लोकसभा का नेता है — प्रधानमंत्री
- * लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा (क्षेत्रफल के अनुसार) निर्वाचन-क्षेत्र है — तद्वाख
- * भारत में लोकसभा का (स्पीकर) अध्यक्ष — चयनित किया जाता है
- * लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है—
— लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा
- * लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है — उपाध्यक्ष को
- * लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है
— लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा
- * प्रो-टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है — सदस्यों को शपथ दिलाना
- * लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) अपने 'कॉस्टिंग वोट' का प्रयोग केवल करते हैं
— जब वोट बराबर-बराबर होने के नाते 'टाय' (Tie) हो

- * संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा — अनुच्छेद 100
- * लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे — जी.वी. मावलंकर
- * प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था—
— जी.वी. मावलंकर
- * लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं — शीरा कुमार
- * लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं — एम. थाम्बी दुरई
- * यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों, तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह
— मत्त-बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं।
- * प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे — पी.ए. संगमा
- * लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखरेख में कार्य करता है — लोकसभा अध्यक्ष
- * लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनु-जाति/अनु-जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है
— वर्ष 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं—
लोकसभा चुनाव - सामान्य वर्ग - 25,000 रु.
अनु. जाति/जनजाति वर्ग - 12,500 रु.
राज्य विधान सभा - सामान्य वर्ग - 10,000 रु.
अनु. जाति/जनजाति वर्ग - 5,000 रु.
- * लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है
— द्वितीय वाचन में
- * निम्न शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं—
I. धन/वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
II. धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में।
III. मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में।

संसद (2)

- * राज्य सभा में होते हैं
— 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं
- * राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है
— उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर
- * राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं—
— राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
- * राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है — 6 वर्ष का

- * राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि—
— इसे विघटित नहीं किया जा सकता है
- * हमारे संविधान के अनुसार, राज्यसभा का कार्यकाल
— समाप्त होने का विषय नहीं है।
- * प्रथम अग्निनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई
— ररगिस दत्त
- * राज्यसभा के संदर्भ में कथन सही है
— इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं
- * राज्यसभा की एकात्मिक शक्ति के अंतर्गत आता है
— नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन
- * राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है—
- (i) राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है।
(ii) राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा।
(iii) ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है।
- * राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, यदि इसके लिए एक संकल्प—
- राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए
- * सही कथन हैं—
1. राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।
2. राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
- * वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं
- संसद को, राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना
- * संसद को राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है — अनुच्छेद 249
- * भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही-सही वर्णित करता है
— इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है
- * सही सुमेलित है—
आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें - 18
महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें - 19
कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें - 12
प. बंगाल में राज्यसभा की सीटें - 16
- (तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 तथा तेलंगाना में 7 हैं)

- * राज्यसभा का अध्यक्ष — उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है।
- * राज्य सभा के वर्तमान समापति हैं — बैकैया नायडू
- * राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में सही है—
(1) उम्र कम-से कम 30 वर्ष होना चाहिए
(2) राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए
- * राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है — 250
- * राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात होगा
- लोकसभा, राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है
- * राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है — मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो
- * राज्यसभा के विषय में सही है—
1. यह भंग नहीं की जा सकती है।
3. प्रत्येक दो वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।

संसद (3)

- * कथन (A): अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
कारण (R): संसद, भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है।
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- * एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है
— दो बार
- * संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए—
— छः महीने का
- * भारत के संविधान में कथित है—
(1) राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा
(2) संसद राष्ट्रपति और दो सदनों में मिलकर बनेगी
- * भारतीय संसद बनती है — लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से
- * संसद का अनन्य भाग नहीं है — उपराष्ट्रपति
- * संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं—
1. अध्यक्ष, लोकसभा
2. उपाध्यक्ष, लोकसभा
3. महासचिव लोकसभा
4. अध्यक्ष, राज्यसभा
- * संसद/विधान सभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है, जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है
— 60 दिन

- * सर्वप्रथम एक सांसद/विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी साठ लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा — **राज्यसभा का**
- * संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है — **अनुच्छेद 105**
- * किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, जब वह — **किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का विगड़ हुआ वर्णन देता है।**
- * लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है — **राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को**
- * सही कथन है — **किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय बर्जना नहीं है**
- * संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है
 1. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु।
 2. संबंधित राज्य की सहमति से।
 3. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में।
 4. राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे।
- * भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती, जब तक — **राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।**
- * अंतर्राष्ट्रीय संघियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है — **बिना किसी राज्य की सहमति से**
- * संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है — **संसद**
- * धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो, किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है — **यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे**
- * सदन का अध्यक्ष, सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है- — **बैठ जाना (Yielding the floor)**
- * 'शून्यकाल' संसदीय व्यवस्था की देन है — **भारत की**
- * लोकसभा में 'शून्यकाल' की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है — **एक घंटा**
- * संसद में शून्यकाल का समय है — **दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक**
- * राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है— — **प्रश्न-उत्तर सत्र**
- * अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है— — **अनु. 253 के अंतर्गत**
- * कथन सही है — **धन विधेयक लोकसभा में पुरःस्थापित किया जाता है।**
- * लोकसभा द्वारा पारित धन-विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती— — **14 दिनों तक**
- * राज्यसभा को 'धन विधेयक' प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए — **14 दिनों के अंदर**
- * जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट (रेफर) किया जाता है, तो इसे पारित किया जाना होता है — **उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा** — **लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर)**
- * संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है— — **एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो**
- * सही कथन हैं—
 1. भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संसदीय है
 2. लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी
 3. भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग (निरसन) बिल को पारित करने के लिए हुई थी
- * भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी— — **दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में**
- * लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है — **साधारण विधि-निर्माण को पारित करने की स्थिति में**
- * कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है — **दोनों में से संसद के एक पटल पर**
- * कथन सही है — **राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।**
- * सही कथन है — **जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है।**

- * भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है
 - भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते
- * भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है
 - भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन
- * भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है
 - भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते
- * भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है
 - भारत की संसद
- * आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं
 - संसदीय स्वीकृति से पूर्व
- * करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है
 - भारत की संचित निधि में
- * संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है
 - अनुच्छेद 110 के अंतर्गत
- * कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं इसका निर्णय करता है
 - लोकसभा अध्यक्ष
- * धन विधेयक के बारे में सही है—
 - लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।
- * सही कथन है
 - धन-संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, राज्यसभा किसी धन-विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है
- * वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है
 - कर से संबंधित उपबंध, उधार (ऋण) लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध
- * कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे—
 - संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है।
- * बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है—
 - बजट के निर्माण में संसद का कोई हस्त्य नहीं होता, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है
- * भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां हैं—
 1. संसद के साम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना
 2. विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना
 3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्राक्धान
 4. संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना
- * संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है
 - आर्थिक कार्य विभाग
- * यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, तो
 - प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है
- * व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई
 - व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर के
- * आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है
 - आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व
- * 'लेखानुदान' संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है
 - निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए
- * संसद में 'लेखा के लिए वोट' आवश्यक होता है
 - जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती।
- * लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर है
 - लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं।
- * व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है
 - अनुदान के अनुरोध के रूप में
- * भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है
 - लोकसभा में
- * सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं—
 1. बजट का प्रस्तुतीकरण
 2. बजट पर चर्चा
 3. विनियोग विधेयक को पारित करना
 4. वित्त विधेयक को पारित करना
- * संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है
 - (1) एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर
 - (2) ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो
 - (3) राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर
 - (4) धन विधेयक पर
- * संदर्भित संबंध संघीय बजट से है
 - कटौती प्रस्ताव
- * पार्लियामेंट द्वारा, 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है
 - 18 वर्ष

- * रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है — संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा
- * भारतीय राजनीति के संदर्भ में, कथन सही है — राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं
- * संसद की एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है — प्राक्कलन समिति
- * प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है — एक वर्ष का
- * सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है — भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
- * संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है — क्रमशः दो और एक के अनुपात में
- * ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है — स्थगन प्रस्ताव को
- * तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है (i) उत्तर मौखिक दिए जाते हैं (ii) पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं
- * भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है — सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु।
- * संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है — हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है।
- * भारतीय संसद का सचिवालय — सरकार से स्वतंत्र है
- * भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है — न्यायिक समीक्षा से
- * भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था — 13-5-2002 को
- * वह कौन राष्ट्रवादी नेता था, जो 1925 में केंद्रीय विधान सभा का अध्यक्ष (स्पीकर) चुना गया — बिट्टल भाई पटेल
- * सही कथन है— — लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- * सही कथन हैं— (1) लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं (2) संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है (3) विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों परिषदों मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है।
- * राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है — आक्लन समिति में
- * सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है — संसद को
- * लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है — लोकसभा के स्पीकर को
- * संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है — शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कॅम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण
- * लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं — 22 (15 लोक सभा तथा 7 राज्य सभा के)
- * लोक लेखा की संसदीय समिति 1. सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है 2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है सही सुमेलन इस प्रकार है
- लोक लेखा समिति वित्तीय समिति
- बाधिका समिति कार्यकारी समिति
- स्टॉक बाजार-स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति
- विभागीय समितियां स्टैंडिंग समिति
- * राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है — इस्टीमेट्स कमेटी से
- * प्राक्कलन समिति गठित की जाती है — लोकसभा के सदस्यों से
- * भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं 1. सार्वजनिक लेखा समिति, 2. प्राक्कलन समिति, 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति
- * संसदीय समिति गठित की गई हैं — सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आंकलनों के बारे में
- * 2-जी स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे — 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से।
- * 2-जी स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे — पी.सी. चाको
- * भारतीय संसद प्रशासन (Administration) पर नियंत्रण करती है — संसदीय समितियों के माध्यम से

संसद (4)

- * 'खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम' प्रथम बार लागू हुआ था — 1954 में
- * सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं — संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय
- * सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है — प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

- * सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है
— **संपूर्ण भारत पर**
- * सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायी होता है
— **निदेशक, प्रबंधक, सचिव**
- * घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है
— **26 अक्टूबर, 2006 को**
- * सामाजिक अधिनियम है
— **एंटी डॉवरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रीवेन्शन ऑफ इमॉरल ट्रेफिक एक्ट**
- * भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों/ विशेषाधिकारों के संदर्भ में कथन सही है
— (i) उपभोक्ताओं को ख़ास की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। (ii) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है।
- * ब्रिगेड ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था — **1871 में**
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 प्रवृत्त हुआ है
— **30 जनवरी, 1990 को**
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं
— **केंद्र सरकार को**
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है
— **एक वर्ष**
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार _____ की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है।
— **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश**
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है, जो आधारित है
— **संरक्षा विभेद का सिद्धांत पर**
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और बसूल करने की शक्ति है
— **राज्य सरकार को**
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में, न्यायालय उपधारित कर सकता है
— **दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य**
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है
— **धारा 6 में**
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन पूर्णतः निषिद्ध है
— **गिरफ्तारी पूर्व जमानत**
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की अत्रिम जमानत प्रतिबंधित है
— **धारा 18 में**
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो _____ रैंक से कम न हो।
— **उप-अधीक्षक**
- * वे शक्तियां जिन्हें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई है
— (i) किसी अपराध के दोषसिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का समग्रहरण (ii) ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना (iii) ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना, जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है।
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायालय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता
— **सामूहिक जुर्माना आरोपित करना**
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है
— **शीघ्र विचारण**
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की 'जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति' के गठन का उपबंध किया गया है
— **धारा 17 के अंतर्गत**
- * सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात है
— (i) स्वशासन प्रदान करना (ii) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना (iii) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना
- * संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई
— **15 जून, 2005 को**
- * सूचना का अधिकार के संबंध में सही है
— **यह एक विधिक अधिकार है**
- * सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष
— **2005 में**
- * सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित है
— **नमित्त शर्मा बनाम भारत संघ**

- * **कथन (A) :** सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है।
- कथन (R) :** इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है।
- (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- * सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है
 - सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच
- * इस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आर.टी.आई. आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का करण अवश्य बताना चाहिए
 - मद्रास उच्च न्यायालय ने
- * अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी होगा
 - ग्राम सभा
- * राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 भारतीय संविधान के प्रावधान के आनुरूप्य अधिनियमित हुए थे
 - स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के आनुरूप्य, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है।
- * भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के संदर्भ में कथन सत्य है
 - इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था

सर्वोच्च न्यायालय

- * भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था
 - 28 जनवरी, 1950 को
- * भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है
 - 31
- * भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी
 - भारतीय संविधान के द्वारा
- * सही कथन है—
 - (i) सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। (ii) सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, जिसमें अपील की जाती है। (iii) सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट-मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय/अदालतों की सुनवाई कर सकता है।
- * भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है
 - संसद में
- * सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, पत्र लिखकर
 - राष्ट्रपति को
- * सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश.....के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।
 - संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने
- * सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है
 - 65 वर्ष
- * उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है
 - संसद द्वारा
- * भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान हैं
 - (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करना पड़ता है। (ii) न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधान मंडल को अपना मत नहीं देना होता है।
- * सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बकालत कर सकते हैं
 - किसी भी न्यायालय में नहीं
- * भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है
 - राष्ट्रपति
- * सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा
 - सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ
- * सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ (Adhoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जब
 - न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता
- * भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है
 - सर्वोच्च न्यायालय में
- * सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश, जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, की संख्या होती है
 - 4
- * उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए
 - पांच
- * केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है—
 - मूल अधिकारिता के अंतर्गत
- * उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं
 - भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद
- * उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी—
 - गोलकनाथ केस में
- * उच्चतम न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढाँचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था
 - केशवानंद भारती वाद में

- * उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि "मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।"
 - गोलकनथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में
- * सही सुमेलित है—
 - इंदिरा साहनी बाद - अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत
 - दिशाखा बाद - अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण
 - मेनका गांधी बाद - अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं हैं।
- * संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है — अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनु. 132 को पढ़ना
- * संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके—
 - अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
- * सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है
 - यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है।
- * भारत में सुधारालोक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है—
 - अनुच्छेद 142 के अंतर्गत
- * उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है
 - अनुच्छेद 137
- * न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय
 - राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है
- * न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है
 - भारत और यू.एस.ए. दोनों में
- * न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है
 - अनुच्छेद 122 के अंतर्गत
- * कोई भी संविधान (संशोधन) कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यदि वह
 - विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है।
- * भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है
 - विधि का शासन
- * संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है
 - सर्वोच्च न्यायालय को
- * भारत के संविधान का अभिरक्षक (Custodian) है
 - भारत का उच्चतम न्यायालय
- * उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है
 - राष्ट्रपति को
- * उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है
 - खंड (1), अनुच्छेद 143 के अंतर्गत
- * विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है
 - संसद को
- * भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है
 - संसद द्वारा विधि बनाकर
- * उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में कथन सही हैं
 - परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर ब्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता।
- * भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है
 - तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का 'अनुलंघनीय मौलिक ढांचा' घोषित किए गए हैं
 - अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227
- * भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है
 - 32 अनुच्छेद के तहत
- * सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम-से-कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए
 - 10 वर्ष
- * "मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा... भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा.....अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा....संविधान और कानून की रक्षा करूंगा।" यह शपथ ली जाती है
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
- * उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं
 - मूल अधिकारों का प्रवर्तन
- * देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार है
 - सर्वोच्च न्यायालय के पास
- * हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है
 - अनुच्छेद 355 को
- * सही कथन है
 - न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका (PIL) के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं।
- * भारत में 'संविधान की मूल संरचना (बुनियादी ढांचा) के सिद्धांत' का स्रोत है
 - न्यायिक व्याख्या

- * भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक "अभिलेख न्यायालय" है। इसका आशय है कि
 - इसके सभी निर्णयों का साक्षात्कार मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है।
 - * अभिलेख न्यायालय माना जाता है
 - उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को
 - * भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है
 - सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है।
 - * उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है
 - राष्ट्रपति के अनुमोदन से
 - * टी.डी.एस.ए.टी. के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है
 - केवल सुप्रीम कोर्ट में
 - * जनहित याचिका की शुरुआत की गई
 - न्यायिक पहल द्वारा
 - * पी.आई.एल. है—
 - पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन
 - * जनहित याचिका (पी.आई.एल) प्रस्तुत की जा सकती है
 - उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में
 - * लोकहित वाद (मुकदमे) की संकल्पना का उद्गम देश है
 - यू.एस.ए.
 - * भारत में 'न्यायिक सक्रियता' संबंधित है
 - जनहित याचिका से
 - * सितंबर, 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई वह न्यायालय है—
 - भारत का सर्वोच्च न्यायालय
 - * यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा
 - * उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक 'पिंसबंद तोता' है
 - कोयला आवंटन घोटाला वाद में
- ## राज्यपाल
- * संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्राक्घानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि -
 - इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था।
 - * राज्य का राज्यपाल मंत्रिमंडल के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है—
 1. विधान सभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।
 2. मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए।
 3. भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए।
 4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए।
 - * राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है
 - अनुच्छेद 200 के अधीन
 - * राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष/संवैधानिक प्रमुख है
 - राज्यपाल
 - * जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है
 - भारत का राष्ट्रपति
 - * भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही हैं—
 - उसकी आयु कम-से-कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
 - * राज्यपाल के संबंध में सही कथन हैं—
 - राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्यापक या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है।
 - * राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है
 - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
 - * किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सत्य है—
 - (a) वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा है
 - (b) वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है
 - (c) सामान्यतया वह पांच वर्ष तक पद पर रहता है
 - * सही कथन है
 - भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है
 - * जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे
 - इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अर्धरहित करें।
 - * किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं
 - भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।

- * किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी आर्डिनैस का अनुमोदन होना आवश्यक है — राज्य की विधायिका द्वारा
- * राज्यपाल की नियुक्ति करता है — भारत का राष्ट्रपति
- * किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद — 155 के तहत होती है
- * राज्यपालों के संदर्भ में कथन सत्य है
 - (i) वह राज्य की विधायिका का अंग होता है।
 - (ii) वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है।
 - (iii) उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं।
- * कथन (A): "राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"
 - कारण (R): "राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है।"
 - (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- * राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं — कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से
- * राज्यपाल उत्तरदायी होता है — राष्ट्रपति के प्रति
- * भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है — राज्यपाल
- * भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्राक्धान नहीं है — राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध
- * स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनीं— — सरोजिनी नायडू (उ.प्र.)
- * पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थीं — पद्मजा नायडू
- * प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, — सरोजिनी नायडू की स्मृति में
- * राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था — रघुकुल तिलक थे
- * भारत में राज्य विधानपालिकाओं (State Legislatives) का उच्च सदन है — विधानपालिका परिषद
- * विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है — 4 माह तक
- * राज्य में धन विधेयक (मनी बिल) प्रस्तुत किया जा सकता है — केवल विधानसभा में
- * राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, बगैर — राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के
- * राज्य विधान परिषद का प्राक्धान भारतीय संविधान में रखा गया है — अनुच्छेद 171 के अंतर्गत
- * राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है — संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा
- * किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्राक्धान है, भारतीय संविधान के— — अनुच्छेद 169 में
- * भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है — राज्य विधानसभा के उत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा
- * उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है — कुल सदस्यों का 1/6
- * इनको भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है — राज्य विधान परिषदों को
- * यहां अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 में उसके लिए उपबंध है — मध्य प्रदेश
- * राज्य विधान परिषद के विषय में सही है—
 - (i) यह एक स्थायी सदन है।
 - (ii) वह भंग नहीं किया जा सकता।
 - (iii) प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
 - (iv) इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
- * भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्राक्धान प्रस्तुत करता है — अनुच्छेद 170
- * अनुच्छेद 170 के उस प्राक्धान का अपवाद है, जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में साठ से कम सदस्य नहीं होंगे — सिक्किम
- * भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं — 500
- * राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है — भारत का निर्वाचन आयोग
- * विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है — उत्तर प्रदेश में

राज्य विधानमंडल

- * मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है-
 - (i) वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है।
 - (ii) वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
 - (iii) उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है।
- * भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है-
 - राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है

- * राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है — राज्यपाल
- * विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु विहित की गई है — 25 वर्ष
- * यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) पद त्यागना चाहे, तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए — उपाध्यक्ष को
- * विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष (स्पीकर) पद पर बना रहता है — विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक।
- * बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है — छः माह तक
- * राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है — राज्य विधानसभा द्वारा
- * राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है — राज्यपाल द्वारा
- * सही कथन है — कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हिव नहीं होगा, यदि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम हो।
- * भारत में एकमात्र राज्य है, जहां "सामान्य (कॉमन) सिविल कोड" लागू है — गोवा
- * वर्ष 1956 में पुनर्गठित इतने राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं — 5
- * किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है — (i) मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। (ii) सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। (iii) मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं।
- * मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं— (i) मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। (ii) मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। (iii) मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, किंतु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष रखता है।
- * मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है — अनुच्छेद 167
- * जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य-अवधि होती है — छह वर्ष
- * भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थीं — उत्तर प्रदेश में
- * भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी — सुचेता कृपलानी

- * जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में 'सदर-ए-रियासत' से 'राज्यपाल' में बदल दिया गया — जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठें संशोधन द्वारा
- * राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेती है

I. भारत के राष्ट्रपति के

II. राज्यसभा के सदस्यों के

III. राज्य विधान परिषद के सदस्यों के

- * 'राज्य की आकस्मिक निधि' की स्थापना के लिए उत्तरदायी है — किसी राज्य का विधानमंडल
- * सही कथन है — किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय

- * उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं — राज्य की समेक्षित निधि से
- * उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है — 62
- * सही कथन है— (i) पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है।
- * भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है— — चौबीस
- * जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, तो वह अधीन होता है— — उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के
- * उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं — संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार
- * यह फैसला दिया है कि एक ही बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है — इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- * अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है — कलकत्ता
- * एक से अधिक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए है — बंबई उच्च न्यायालय
- * मार्च, 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं — मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर

- * उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं (संघ राज्य-क्षेत्र शामिल नहीं हैं)
नोट — संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं—
- (1) गुवाहाटी उच्च न्यायालय - अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मिजोरम। (2) बंबई उच्च न्यायालय - महाराष्ट्र और गोवा। (3) पंजाब एवं हरियाणा - पंजाब और हरियाणा। (4) तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय - आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना।
- * उच्च न्यायालयों में से सबसे अधिक "बेंच" हैं
नोट — कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और दो बेंच ग्वालियर और इंदौर हैं, मुंबई उच्च न्यायालय की मूल पीठ बंबई और तीन बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और तीन बेंच कोहिमा, आइजोल, ईटानगर हैं। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थीं, परंतु मार्च, 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात् अब तीन बेंच शेष रह गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न में बंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3-3 बेंचें हैं।
- * उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं
— मूल अधिकारों का संरक्षण
- * एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह, ऐसा कार्य करे, जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट (याचिका) को कहा जाता है
— बैंडमस
- * जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो उसे कहते हैं—
— परमादेश
- * राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है
— परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार
- * रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है
— प्रतिषेध (प्रोहिबिशन)
- * एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण (Certiorari) रिट जारी की जाती है
— एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण (रिव्यू) हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे।
- * एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है
— उत्प्रेषण
- * कथन (A) : न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना, न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है।
कारण (R) : न्यायिक सक्रियता वाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।
— A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- * कथन (A) : जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है।
कारण (R) : जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकें जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है।
— (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- * कथन (A) : भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है।
कारण (R) : भारतीय संविधान "उधार वस्तुओं से भरा बैला है"। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए
— (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- * कथन (A) : भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है।
कारण (R) : सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है।
— (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- * बाबरी मस्जिद/सम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ न्यायपीठ) के समक्ष है, का प्रकार है -
— स्वत्वाधिकार मुकदमा (Title suit)
- * सही कथन है—
— भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है।
- * एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संशोधित करता है
— राष्ट्रपति को
- * 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया
— न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ
- * भारत में चलित न्यायालय (Mobile Court) इसका मानसपुत्र है—
— डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
- * प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है
— तीन माह तक
- * 'विधि आयोग' के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि "प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिये"
— न्यायाधीश एच.आर. खन्ना
- * 'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के संदर्भ में सही है
— वह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है।

केंद्र-राज्य संबंध

- * भारत में केंद्र-राज्य संबंध प्रभावित होते हैं—
 1. संविधान के प्रावधानों से
 2. नियोजन प्रक्रिया से
 3. राजनीतिक हिंसे के अंतर्विरोध से
 4. हुकम चलाने की इच्छा प्रबलता से
- * केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है — अनुच्छेद 268-281 के अंतर्गत
- * भारत में केंद्र-राज्य संबंध निर्भर करते हैं
 1. संवैधानिक प्रावधानों पर
 2. परंपराओं तथा व्यवहारों पर
 3. न्यायिक व्याख्याओं पर
 4. वातवीत के लिए यंत्रविन्यास पर
- * एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं—
 1. संघ और राज्यों के बीच संबंध
 2. राज्यों के मध्य संबंध
 3. समन्वय के लिए तंत्र
 4. विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र
- * केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है, शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं — अनुच्छेद 245 तथा 246
- * भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है — राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से
- * अनुच्छेद-249 के खंड (1) के अंतर्गत पास्ति प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रहेगा — एक वर्ष से अधिक समय के लिए
- * वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, उल्लिखित हैं — समवर्ती सूची में
- * केंद्र-राज्य संबंध उल्लिखित हैं — 7वीं अनुसूची में
- * विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूचियों में है — सातवीं
- * केंद्र-राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं — भाग XI में
- * भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं — संसद में
- * भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को — संघीय सरकार को दिया है
- * केंद्र-राज्य संबंधों को विशेष रूप से 'म्युनिसिपल संबंध' कहा गया है — वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के निबंधन के प्रसंग में
- * संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में है — अनुच्छेद 355 में
- * भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विधित्तर संस्था/संस्थाएं हैं — राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन
- * झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ — 8 अगस्त, 1995 को
- * भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है — अनुच्छेद 263 के अनुसार
- * अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है — संवैधानिक
- * सही सुमेलित है— अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 राष्ट्रीय जल नीति, 1987
- * क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है — संसदीय कानून द्वारा
- * कथन (A): केंद्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। कारण (R): राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। — (A) और (R) दोनों अपनी जगह सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- * विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है— अनुच्छेद 265 में कहा गया है
- * सरकारिया आयोग गठित हुआ था, समीक्षा करने के लिए — संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की
- * सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है — केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से
- * अभिकथन (A): सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण (R): जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- * स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद, जो 'अंतर-सरकारी परिषद्' के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया — सरकारिया आयोग ने
- * भारत में संघ-राज्य संबंध से संबंधित है — सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग
- * संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं — नहीं
- * राज्य सरकारों को कृषि आय कर समनुदेशित करता है — भारत का संविधान
- * एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है — कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर

आपात उपबंध

- * भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? — अनुच्छेद 355 के अंतर्गत
- * भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है — युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह
- * आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है — आंतरिक अशांति
- * भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय आपातकाल' की घोषणा की जा सकती है — अनुच्छेद 352 के अनुसार
- * इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है—
— बाह्य आक्रमण, राज्यों में सैधानिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट
- * भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं (अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त)
— अनुच्छेद 359 के अंतर्गत
- * भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है
नोट : अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं जबकि अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, 44वां संविधान संशोधन) को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। यहां उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालयों द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है।
- * प्रायः राज्यों में 'राष्ट्रपति शासन' लागू किया जाता है — गवर्नर के सतह पर
- * इस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान है
नोट : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में सैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू व कश्मीर की विशेष स्थिति (अनुच्छेद 370) को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन (1964 से) के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में सैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया है।
- * संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कथन सही हैं—
(i) राज्यों में सांविधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है।
(ii) इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
(iii) इस उद्घोषणा का दो माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए।

- * संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है — 1 माह अंतराल में
- * "राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ घोखा है" कहा था — के.एम. नम्बियार ने
- * भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन है — वित्तीय आपात की उद्घोषणा दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है — अनुच्छेद 360 का
- * भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक की गई है — कभी नहीं
- * भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है — तीन प्रकार के
- * राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि — आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल एक वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है।
- * राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है — 3 वर्ष तक
- * आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है — संसद द्वारा

वित्त आयोग

- * सामान्य रूप में नास्त में प्रति पांच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है — केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए
- * संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है — वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर
- * भारत में, शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर कर 1. संघ द्वारा लगाए जाते हैं
2. राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं
- * वित्त आयोग का मुख्य कार्य है — केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना
- * वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है: —राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से
- * भारत में वित्त आयोग का कार्य है — आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहाय्यार्थ अनुदान निर्धारण

- * कथन (A): राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
कारण (R): संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता।— (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
- * संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को — राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
- * 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे — सी. रंगराजन
- * 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे — विजय केलकर
- * 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे — वाई.वी. रेड्डी
- * वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा — भारत का राष्ट्रपति
- * वित्त आयोग का गठन किया जाता है, प्रत्येक — पांचवें वर्ष
- * राज्य वित्त आयोग के संबंध में सही है — यह एक संवैधानिक संस्था है
- * संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं—

नोट : अब तक 14 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 14 वें वित्त आयोग का गठन जनवरी, 2013 में वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर, 2014 को सौंपी।

- * वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, और — चार अन्य सदस्य

योजना आयोग

- * योजना आयोग का अंत किया — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
 - * योजना आयोग की स्थापना हुई थी — 15 मार्च, 1950
 - * योजना आयोग की स्थापना की गई — संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर
 - * संविधानेतर संस्था है — नीति आयोग
 - * वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था — एम.वी. माथुर ने
 - * संवैधानिक निकाय नहीं है — योजना आयोग
 - * इन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है
1. राष्ट्रीय विकास परिषद्
 2. योजना आयोग
 3. क्षेत्रीय परिषदें
- * भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे — पंडित जवाहरलाल नेहरू
 - * योजना आयोग के 'पदेन' अध्यक्ष हैं — प्रधानमंत्री
 - * नीति आयोग के विषय में सही है — (i) इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है।
(ii) इसका गठन जनवरी, 2015 में किया गया था।
(iii) यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है।

- * योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्त्व का दर्जा दिया गया है — भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान
- * कथन (A) : "योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है", केवल संघ हेतु नहीं, अपितु राज्यों हेतु भी।
कारण (R) : यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। — (A) एवं (R) दोनों सही हैं, परंतु (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है (A) का
- * राष्ट्रीय विकास परिषद्—
- 1. राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है।
- 2. राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है।
- 3. राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशानिर्देश प्रदान करती है।
- * राष्ट्रीय विकास परिषद् की रचना करते हैं — प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रिगण, राज्यों के मुख्यमंत्री
- * राष्ट्रीय विकास परिषद् का मुख्य संबंध है — पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से
- * राष्ट्रीय विकास परिषद् की अध्यक्षता करता है — भारत का प्रधानमंत्री
- * भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद् गठित की गई थी — 6 अगस्त, 1952 को

लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग

- * भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था — प्रशासनिक सुधार आयोग ने
- * राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी — भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70)
- * ओगब्युड्समैन का भारतीय प्रतिमान है — लोकपाल
- * संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था — 1968 में
- * उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है — द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में
- * सर्वप्रथम लोकयुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी — महाराष्ट्र में
- * * उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है — राज्यपाल को
- * 2011 में लोकयुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है — उत्तराखंड
- * वोहरा समिति.....के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। — राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ

- * वह समिति, जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी — **वोहरा समिति**
- * भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी — **राजमन्नार आयोग ने**
- * 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था — **अनुच्छेद 123**
- * मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का उद्देश्य था — **मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन**
- * राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं — **लोक सभा का अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष का नेता तथा राज्य सभा में विपक्ष का नेता**
- * भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन है—
— इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हूना चाहिए, इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है।
- * मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में 'लोक सेवक' की परिभाषा दी गई है — **धारा 2(M) के अंतर्गत**
- * कथन (A): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो।
कारण (R): उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयुपर्यंत पर (जो भी पहले हो) धारित करता है।
— **(A) तथा (R) दोनों सही हैं।**
- * राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है — **राज्यपाल द्वारा**
- * राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है — **मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना।**
- * संवैधानिक संस्था नहीं है — **मानवाधिकार आयोग**
- * संवैधानिक प्राधिकरण हैं—
1. राज्य निर्वाचन आयोग, 2. राज्य वित्त आयोग, 3. जिला पंचायत
- * संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन सही हैं— — **इसकी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रकृति की होगी, इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम. एन. वैकटचेतैया कर रहे हैं**
- * संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी, 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष हैं — **एम.एन. वैकटचेतैया**
- * केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल होता है — **5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक**
- * स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया, वह था — **मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता**
- * मंडल आयोग, जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, को गठित करने वाले थे — **मोरारजी देसाई**
- * मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई — **1980 में**
- * वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है — **धार्मिक कारण**
- * राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है — **राज्यपाल द्वारा**
- * दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है — **भारत के राष्ट्रपति के द्वारा**
- * राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है — **सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर**
- * किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है — **भारत के राष्ट्रपति अनुमोदन से**
- * लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है — **अनुच्छेद 317 के अंतर्गत**
- * भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है — **इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना-देना नहीं है**
- * संघ लोक सेवा आयोग एक — **संवैधानिक संगठन है**
- * संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है — **राष्ट्रपति को**
- * यूनिफ़ॉर्म पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है — **रोज वैथ्यू**
- * उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भास्ति होते हैं — **राज्य की संचित निधि पर**
- * भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई, वह था — **गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919**

अस्थायी विशेष प्रावधान

- * भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है — **अनुच्छेद 371 में**
- * भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है। वह राज्य है— — **जम्मू-कश्मीर**
- * भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-ख में विशेष उपबंध प्रावधानित हैं — **असम के लिए**
- * संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है — **महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए**
- * भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है — **कश्मीर का अलग संविधान है**
- * भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है — **एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध**

- * भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है
— जम्मू-कश्मीर राज्य से
 - * भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू-कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं, वे हैं -
— अनुच्छेद 1 एवं 370
 - * जम्मू एवं कश्मीर का 'सदर-ए-रियासत' पदनाम बदल कर 'राज्यपाल' कर दिया गया
- नोट : जम्मू एवं कश्मीर संविधान में छठें संविधान संशोधन अधिनियम, 1965 द्वारा सदर-ए-रियासत नाम बदलकर राज्यपाल तथा वजीर-ए-आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया।

चुनाव आयोग

- * मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन हैं—
— (i) मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है, जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है।
(ii) मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।
- * भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है
— सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष
- * भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है
— 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
- * मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है
— संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर
- * निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है
— मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है
— राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है
— अनुच्छेद 324 के अंतर्गत
- * भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं—
I. संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना।
II. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना।
III. निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण।
- * राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है
— भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा
- * भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं
1. वयस्क मतधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली।
2. एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुषांगिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली।
- * भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है
— निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना
- * संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा — भारत के निर्वाचन आयोग की
- * यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि (जमानत राशि) खो देता है, तो उसका अर्थ है कि
— निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है — संसद द्वारा
- * भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है
— विधिक अधिकार (एक अधिनियम के अंतर्गत)
- * नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया, इस आम चुनाव में
— 1989 के
- * केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई
— 61 वें संशोधन (1989) द्वारा
- * 'निर्गम मत सर्वेक्षण' के विषय में कथन सही है
— निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया।
- * जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में सही हैं
— (i) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि के होने पर दोषसिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी।
(ii) लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अम्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है।
(iii) चुनाव लड़ने वाले किसी अम्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता।
- * दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी
— लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधीन की।

- * दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था
— निर्वाचन सुधारों से
- * उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है, जहां
— द्वि-दलीय प्रणाली विकसित हुई है
- * कथन (A) : संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात् निर्वाचन आयोग को दी गई हैं।
कारण (R) : निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है।
— A और R दोनों सही हैं, किंतु R सही स्पष्टीकरण नहीं है A का
- * निर्वाचन आयोग को 'तीन सदस्यीय आयोग' बनाया गया
— 1989 से
- * इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता
— स्थानीय निकायों का
- * परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन है—
1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।
- * राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है — 25 जनवरी को
- * कथन (A) : आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है।
कारण (R) : आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के व्योम्भित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है।
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R) सही व्याख्या है (A) की
- * आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, निर्वाचन क्रियाप्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है — अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को
- * कथन (A) : राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है।
कारण (R) : ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। — (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

राजनीतिक दल

- * भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है, यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम—
— चार राज्यों में
- * किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि
— वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है।

- * किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है, जब वह—
(i) उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं चार या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत मत और साथ ही कम से कम चार लोकसभा सीटें प्राप्त हों।
(ii) उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2 प्रतिशत सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों।
(iii) वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो।
- * 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' में 'राष्ट्रीय' शब्द प्रभावित था
— ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से
- * 1999 में विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ
— कांग्रेस पार्टी के
- * राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है :
1. यह बयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
2. प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी।
3. धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा।
4. राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी।
- * भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे
— ए.बी.वाजपेयी
- * 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' का संस्थापक थे — बी.आर. अम्बेडकर
- * डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना की थी — ऑल इंडिया सिक्क्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी
- * सही सुमेलन इस प्रकार है—
(राजनैतिक दल) (गठन वर्ष)
- सी.पी.आई. 1920
- सी.पी.एम. 1964
- ए.आई.ए.डी.एम.के. 1972
- तेलगूदेशम 1982
- * भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सी.पी.आई. और सी.पी.आई.एम. में हुआ था — 1964 में
- * कथन (A) : भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ बायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं
कारण (R) : वह बहुत से चीजों की वृहद विस्तार में चर्चा करता है।
— दोनों A और R सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

- * कथन (A) : भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनैतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले।
कारण (R) : बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है।
— A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
- * कथन (A) : संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
कारण (R) : चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दल, बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके तैंतीस प्रतिशत को, महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं।
— A गलत है, परंतु R सही है।
- * भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है — चुनाव आयोग को
- * भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं—
1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।
2. राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है।
3. राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है, जिसे चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है।
- * कथन (A) : भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है।
कारण (R) : अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं।
— A तथा R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
- * आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है
— दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय-समय पर हो।
- * दल-बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ, वह थी
— 15 फरवरी, 1985
- * राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष
— 1985 में
- * दल परिवर्तन विरोधी विधि 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था
— जम्मू एवं कश्मीर राज्य में
- * लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए
नोट : लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 545 का न्यूनतम 10% अर्थात् 54.5 या 55 सदस्य संबधित पार्टी या गठबंधन का होना चाहिए।

- * साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से 'भू-पोर्टम' आंदोलन चलाया था
— आंध्र प्रदेश में
- * 'कामराज योजना' का उद्देश्य था
— भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना
- * कथन (A) : भारत में लिखित संविधान है।
कारण (R) : शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आवंक्षाओं का संकेतक है।
— (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

संविधान संशोधन

- * कथन सही है
— मिनर्वा मिल्स बाद, 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है।
- * संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति "सहमति देनी होगी" शब्द से स्थापन करके संशोधन द्वारा छीन ली गई है
— चौबलिसवां संशोधन
- * भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है
— संविधान संशोधन विधेयक
- * भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है
— अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत
- * भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है
— या तो लोकसभा में या राज्यसभा में
- * भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा समुष्टि आवश्यक है—
1. संविधान के संघीय प्रावधान
2. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार
3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया
- * वे विषय, जिन पर कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधानिक संशोधन संभव है — (1) राष्ट्रपति का निर्वाचन
(2) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
(3) सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची
- * भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन (Amendment Act) विधेयक लाया गया
— 1951
- * उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब
— विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है।

- * संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, संबंधित था — कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि-भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से
- * भारतीय संविधान में 9 वीं अनुसूची परिवर्धित हुई
 - प्रथम संशोधन द्वारा
- * संविधान का 93 वां संशोधन (विधेयक) संबंधित है
 - 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से
- * 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा का अधिकार' लागू किया गया
 - वर्ष 2010 से
- * अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है
 - 93वें संशोधन के अंतर्गत
- * सही सुमेलन इस प्रकार हैं
 - (i) 69वां संविधान संशोधन : दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा;
 - (ii) 75वां संविधान संशोधन : राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना
 - (iii) 80वां संविधान संशोधन : दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना
 - (iv) 83वां संविधान संशोधन : उरुपाबल प्रदेश में पंचायतों में अनु. जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहां का समाज आदिवासी समाज है।
- * अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियां' शब्द जोड़ा गया
 - 97वां संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा
- * दिल्ली 'नेशनल कैपिटल क्षेत्र' बना
 - 69वां संशोधन द्वारा
- * पहली बार संविधान में दल-बदल विरोधी प्रावधान किया गया
 - 52वां संशोधन द्वारा
- * भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को संविधान संशोधनों में से प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया
 - 58वां संशोधन, 1987 के द्वारा
- * मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है
 - 61वां संशोधन
- * भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है
 - लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से
- * भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि
 - संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता।
- * भारत में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है
 - संसद
- * सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया
 - गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में
- * लघु संविधान कहा गया था
 - 42वां संविधान अधिनियम को
- * यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39(b) और (c) में वर्णित हैं, प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है
 - 25वां संशोधन
- * संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है
 - 42वां
- * केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार, क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा—
 - 91वां संविधान संशोधन
- * सिक्किम एक नया राज्य बना
 - 36वें संशोधन द्वारा
- * मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया
 - 53वां संवैधानिक संशोधन द्वारा
- * 'शिक्षा का अधिकार' प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21-A संविधान में जोड़ा गया है
 - 86वां संशोधन द्वारा
- * 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार से है
 - सहाय्यारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन
- * सही सुमेलन इस प्रकार है—
 - (i) 13वां संशोधन — नगालैंड
 - (ii) 18वां संशोधन — राज्य को पुनर्निभाषित किया गया
 - (iii) 39वां संशोधन — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती
 - (iv) 52वां संशोधन — दल-बदल अधिनियम

राजभाषा

- * यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा
 - अनुच्छेद 350-क में
- * सही कथन है—
 - बोझे संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है।
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम 'राजकीय भाषा आयोग' का गठन हुआ था
 - 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में
- * भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा चार भाषाएं जोड़ी गईं, जिसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई
 - संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम
- * संविधान की आठवीं सूची में नहीं है
 - भोजपुरी

- * 71वें संशोधन से संविधान की आठवीं अनुसूची में तीन भाषाएं जोड़ी गई थीं — **नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी**
- * भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है — **22**
- * संविधान में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है — **अनुच्छेद 345 में**
- * संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है — **उत्तराखंड ने**
- * भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्राक्धान का संशोधन हो सकता है — **कम से कम 2/3 बहुमत से**
- * संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं — **हिंदी, इसके बाद बंगाली**
- * भारतीय भाषाओं को, मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का, सही अवरोही क्रम है — **बंगाली, तेलुगू, मराठी, तमिल**
- * हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग है — **40**
- * विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं — **मंदारिन के**
- * भाषा बलूचिस्तान की है, किंतु भाषाशास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है — **ब्राहुई**

पंचायती राज व सामुदायिक विकास

- * पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है — **राज्य का विधानमंडल**
- * पंचायतों के संबंध में सही कथन हैं — **भारत के संविधान के भाग IX में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है।**
- * पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है — **राज्य सरकार द्वारा**
- * पंचायती राज सम्मिलित किया गया है — **राज्य सूची में**
- * पंचायत चुनाव होते हैं — **प्रत्येक पांच वर्षों में**
- * पंचायतों से संबंधित है — **राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सभी पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित होगा, एक पंचायत के भंग होने के छः माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा।**
- * पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए 'वित्त आयोग' का गठन करता है — **संबंधित राज्य का राज्यपाल**
- * भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबद्ध 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे — **पी.वी. नरसिंहराव**

- * पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्राक्धान किया गया — **1993 में**
- * कथन (A) : पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रिया-कलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है।
कारण (R) : ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं। — **(A) सही है, परंतु (R) गलत है।**
- * 'पंचायती राज व्यवस्था' को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है — **73वां संविधान संशोधन**
- * भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है — **73वें संशोधन के अंतर्गत**
- * पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका/शक्ति है-
1. ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है।
2. ग्राम सभा के पास लघु बनेपज का स्वामित्व होता है।
- * पंचायती राज एक व्यवस्था है —
1. स्थानीय स्तर पर स्वशासन की।
2. जैव-संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की।
3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की।
- * 'ग्राम सभा का अभिप्राय है — **ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग**
- * अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता करता है — **उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए**
- * पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है — **विकास में जन-भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण**
- * राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है — **अनुच्छेद 40**
- * भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है — **ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में**
- * पंचायती राज को.....के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया — **भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन**
- * मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया है — **अनुच्छेद 43**
- * सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं — **इनमें सरकार की तीन श्रेणियां होती हैं, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं**

- * पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है
 - ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण
- * पंचायती राज से संबंधित सही कथन है—
 - (i) पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है।
 - (ii) यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है।
 - (iii) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके बह्वच को बढ़ाता है।
- * पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है
 - लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना
- * सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है
 - स्थानीय जनता की
- * भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है
 - शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास
- * CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था
 - बलवंत राय मेहता समिति
- * सही सुमेलित है—

सूची-I (समितियाँ)	सूची-II (सुझाव)
A. बलवंतराय मेहता	1. त्रिस्तरीय पद्धति
B. अशोक मेहता	2. द्विस्तरीय पद्धति
C. एल.एम. सिंघवी	3. स्थानीय स्वशासन पद्धति
D. जी.बी.आर. राव	4. प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार
- * बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई
 - राजस्थान में
- * भारत के 'पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार (शिल्पी)' कहा जाता है
 - बी.आर. मेहता
- * भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और.....में प्रारंभ की गई थी।
 - आंध्र प्रदेश
- * प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को किया गया था
 - नागौर (राजस्थान) में
- * बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार :
 - जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था
- * पंचायती राज से संबंधित समितियाँ कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित हैं—
 - बी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.बी. के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति
- * अशोक मेहता समिति ने 'पंचायती राज' के लिए संस्तुति की थी
 - द्विस्तरीय प्रतिमान की
- * पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी
 - एल.एम.सिंघवी कमेटी द्वारा
- * संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं
 - ग्यारहवीं सूची में
- * संविधान के 73वें संशोधन ने प्राक्घान किया है—
 1. पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए
 2. महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए
 3. राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं
 4. 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण।
- * भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय निर्धारित किए गए हैं
 - 29
- * राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही है
 1. राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है।
 2. राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है।
- * पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है—
 - I. नगर पंचायत, II. ग्राम पंचायत, III. क्षेत्र पंचायत
- * 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है—
 - मध्य प्रदेश
- * 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 निर्दिष्ट करता है -
 - देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना
- * महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान (Indian Constitution) में संशोधन करके दिया गया है, वह है -
 - 1992 का 73 वां संशोधन
- * संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के एक-तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है
 - अनुच्छेद 243 घ
- * 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल, 1993 से देश में प्रभावी हुआ है, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा
 - स्वशासन व्यवस्था
- * पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है
 - ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना
- * 'तृण मूल लोकतंत्र' से संबंधित है
 - पंचायती राज पद्धति

- * पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी
 - लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए
- * पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं—
 - ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद
- * तीन सौपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है
 - भाग 9 (ix) में
- * एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है
 - राज्य सरकार द्वारा
- * एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, यदि उसने पूर्ण कर ली है
 - 21 वर्ष की आयु
- * सही कथन है
 - पंचायत के समय पूर्व बंग होने के पश्चात् पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है।
- * वह कालेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद (Municipal Council) में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि
 - उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो।
- * भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है
 - न्यायिक पुनर्वीक्षण (Judicial Review)
- * पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है
 - बिहार में
- * स्थानीय शासन की विशेषता है—
 - (a) वैधानिक स्थिति
 - (b) स्थानीय समुदाय की भागीदारी
 - (d) कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति
- * राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है—
 - अनुच्छेद 243 (आई) के अनुसार
- * किसी राज्य के राज्यपाल को, उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है
 - राज्य वित्त आयोग
- * शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया
 - 74वां संशोधन द्वारा
- * मेयर का कार्यकाल होता है
 - 5 वर्ष का
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ZJ) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है
 - 21
- * राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों (Local Bodies) पर नियंत्रण नहीं होता
 - नागरिकों की शिकायतों में
- * नगरपालिकाओं से संबंधित है
 - भाग IX A
- * सही सुमेलन है

उप-प्रभाग स्तर पर जिला परिषद	- असम
बंडल प्रजा परिषद	- आंध्र प्रदेश
जनजातीय परिषद	- मेघालय
ग्राम पंचायतों का अभाव	- मिजोरम
- * जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं
 - 20 और 5
- * कथन (A): स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है।
 - कारण (R) : संविधान के 73 वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है।
 - दोनों A और R सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
- * कथन (A) : स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है।
 - कारण (R) : संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधन के बावजूद, स्थानीय शासन संविधान के सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है।
 - (A) गलत है, परंतु (R) सही है।
- * यदि पंचायत बंग होती है, तो निर्वाचन होंगे
 - 6 माह के अंदर
- * भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में, कथन सही है
 - (a) राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे, तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है।
 - (b) जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए।
 - (d) उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बचे हुए बात या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है।
- * पंचायती राज संस्था नहीं है
 - नगालैंड में
- * नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही है
 - ये सभी स्थान :
 - जो नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. हो
- * किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है
 - संबंधित राज्य का राज्यपाल

- * भारत में महानगर योजना समिति
 1. भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है।
 2. उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारम्भ तैयार करती है।
- * भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है
 - अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से
- * पंचायत की संरचना के संबंध में सही है—
 1. किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा।
 2. ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी।
 3. ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे।
- * पंचायत समिति के सदस्य
 - जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं
- * पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा
 - राज्य के राज्यपाल द्वारा
- * पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है
 - खंड स्तर पर
- * उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है
 - जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही
- * उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है
 - (i) अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा।
 - (ii) अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से।
- * 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है
 - किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य
- * महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, सम्पादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है
 - ग्राम पंचायत की
- * सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है
 - राष्ट्रीय प्रसार सेवा

कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध

- * कथन (A) : 'अल्पसंख्यक' शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है।
कारण (R) : अल्पसंख्यक आयोग सांविधानिक निकाय नहीं है।
— A और R दोनों सही हैं, परंतु A की सही व्याख्या R नहीं करता है।
- * सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं — मध्य प्रदेश में
- * अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान किया गया है
 - 338 और 338A के अंतर्गत

- * अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कथन सही हैं—
 - (a) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई हैं।
 - (b) इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है।
 - (d) कोई जनजाति, राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है।
- * अनुसूचित जनजाति का दर्जा : — धर्मनिष्ठा से तटस्थ है
- * भारत के संविधान में लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है
 - अनुच्छेद 330 में
- * भारतीय संविधान का भाग-16 (अनुच्छेद 330 से 342 तक) संबंधित है
 - लोक सभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से
- * लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है
 - अनुच्छेद 331 के अंतर्गत
- * किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु, शक्ति संपन्न सांविधानिक प्राधिकारी है
 - भारत का राष्ट्रपति

प्रश्न विविधा

- * संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था — 1945 में
- * संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है — 24 अक्टूबर
- * संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है — 5
- * संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में कथन सही है—
 - (a) सभी प्रक्रियेतर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय नौ सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाने आवश्यक हैं और उन नौ में परिषद के स्थायी सदस्यों के सहमति मत होने भी आवश्यक हैं।
 - (b) सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है।
 - (c) निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प पर रोक लगा सके।
- * प्रथम अफ्रीकी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं
 - बुतरोस बुतरोस घाली
- * संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा
 - यू. थॉट का

- * संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं हैं
— अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी
- * संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं
— अटल बिहारी वाजपेयी
- * 'यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स' में कुल अनुच्छेद हैं
— 30
- * अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है
— हेग
- * एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, जो जुड़ हुआ है
— मानव अधिकारों के संरक्षण से
- * श्री आर.एन. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित दो अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे
— बी. आर. राउ व नगेन्द्र सिंह
- * यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है
— एमनेस्टी इंटरनेशनल
- * 'Doctors without Borders (Medecins Sans Frontiers) जो प्रायः समाचारों में आया है, है
— एक गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- * 10 दिसंबर मनाया जाता है
— मानवाधिकार दिवस के रूप में
- * मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है
— मानव होने के नाते मानव-गरिमा पर
- * अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है
— 2 अक्टूबर को
- * अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं
- नोट — अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। इसके लिए 'निर्वाचक मतों' (Electoral College) का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो इस राज्य के सीनेटरों (सदैव 2) तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया (वाशिंगटन डीसी) से 3 सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कालेज अमेरिकी कांग्रेस (प्रतिनिधि सभा + सीनेट) से भिन्न है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल निर्वाचकों की संख्या 538 है।
- * अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी होती है
— न्यू हैम्पशायर में
- * ऋष्यदात्मक (Presidential) शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ
— संयुक्त राज्य अमेरिका में
- * लिखित संविधान की अवधारणा (Concept) ने सर्वप्रथम जन्म लिया
— संयुक्त राज्य अमेरिका में
- * लैरी प्रेसलर संबद्ध हैं
— विल्टन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना
- * 'एशिया की घुरी' विदेश नीति की रणनीति है
— यू.एस.ए. की
- * सी.आई.ए. आसूचना एजेंसी है
— यू.एस.ए. की
- * संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई
— ब्रिटेन में
- * ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र है
— प्लीट स्ट्रीट
- * विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव आयोजित हुआ
— ब्रिटेन 1982
- * सही कथन है
— रूस की संसद (पार्लियामेंट) फेडरल असेम्बली कहलाती है
- * तास समाचार एजेंसी है
— रूस की
- * चीन की संसद जानी जाती है— नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से
- * 'प्रिंसलिंग' नाम से जाना जाता है
— चीन के राजनैतिक नेतृत्व को
- * चीन की समाचार एजेंसी का नाम है
— न्यू चाइना न्यू एजेंसी
- * ISI का पूरा नाम है
— इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस
- * 'डॉन' समाचार-पत्र है
— पाकिस्तान का
- * 'मोसाद' है
— इस्राइल गुप्तचर संगठन
- * प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की, थे
— जवाहरलाल नेहरू
- * जापान की संसद को कहा जाता है
— डाइट
- * इस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है— फ्रांस की
- * सही कथन है
— राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संघि या संविधान नहीं है
- * वह अपराध, जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता
— आत्महत्या
- * 'फोर्थ एस्टेट' (Fourth Estate) या 'चतुर्थ स्तंभ' है
— प्रेस
- * "पंचशील" का सिद्धांत है
— शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक-दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप
- * सही सुमेलित है—
सूची I (कृत्यकारी)
(A) भारत का राष्ट्रपति
(B) सर्वोच्च न्यायालय के जज
(C) संसद सदस्य
(D) संघ के मंत्री
- सूची II (शपथ या प्रतिज्ञान)
1. भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा
2. संविधान और विधि की मर्यादा
3. कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन
4. सूचना की गोपनीयता बनाए रखना

- * संविधानेतर अधिकार का अर्थ है
— वह शक्ति जो संविधान सममत नहीं है
- * सही कथन हैं—
1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं।
2. जिस राजनैतिक दल को चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है, वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है।
3. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा किया जाता है।
4. संज्ञेय अपराध वह अपराध है, जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है।
- * जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं—
(i) कानून व व्यवस्था बनाए रखना।
(ii) पुलिस पर नियंत्रण रखना।
(iii) विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना।
- * सही सुमेलित है—
कानून के समक्ष समानता — नागरिकों और गैर-नागरिकों को प्राप्त नए राज्य का निर्माण — संसद की शक्ति
सरकारी नौकरी में अक्सर— केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त की समानता
- * सरोज जईवाला विख्यात हैं
— अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ के रूप में
- * वह भारतीय, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वे— — नारायण देसाई थे
- * जून, 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए — श्री नंदन नीलेकनी
- * सही सुमेलन इस प्रकार है—
भारत का उप-राष्ट्रपति - राज्य सभा
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - लोक लेखा समिति
भारत का महाधिवक्ता - उच्चतम न्यायालय
भारत का महान्यायवादी - लोक सभा की बैठक
- * सीमा प्रबंध विभाग, केंद्रीय मंत्रालयों में से एक का विभाग है
— गृह मंत्रालय का
- * मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग हैं—
(a) आंशिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
(b) माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग
(c) तकनीकी शिक्षा विभाग
- * खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के अधीन कार्यरत है
— मानव संसाधन विकास मंत्रालय के
- * अभिकथन (A): भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है।
कारण (R): अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। — कथन सही है, पर कारण गलत है।
- * भारतीय प्रेस काउंसिल एक — अर्द्ध न्यायिक-वैधानिक संस्था है
- * भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है — असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व
- * सिक्किम के संबंध में सही हैं—
I. 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था।
II. इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है।
III. इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं।
- * राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई — 1982 में
- * इन समझौतों का सही कालानुक्रम है—
— ताशकंद समझौता, भारत-सोवियत संधि, शिमला समझौता, फरक्का समझौता
- * भारत-पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था
— दिसंबर, 1971 में
- * सही सुमेलित है—
A. ऑपरेशन चेकमेट - श्रीलंका
B. ऑपरेशन कैक्टस - मालदीव
C. ऑपरेशन ब्लू स्टार - पंजाब
D. ऑपरेशन सिद्धार्थ - बिहार
- * 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' आदर्श है
— ऑल इंडिया रेडियो का
- * भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी
— 1980 के दशक में
- * आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है
— हफीज मोहम्मद साईद
- * सुमेलित है—
(a) एपिको आंदोलन - पी. हेगडे
(b) चिपको आंदोलन - एस.एल. बहुगुणा
(c) नर्मदा बचाओ आंदोलन - मेधा पाटकर
(d) शांत घाटी आंदोलन - डॉ. सलीम अली
- * सही सुमेलित है—
(a) दक्षिणी वायुसेना कमान : तिरुवन्तपुरम
(b) पूर्वी नौसेना कमान : विशाखापत्तनम
(c) आरमर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल : महाराष्ट्र
(d) आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल : लखनऊ

- * भारतीय नौसेना में, सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष होता है — कमांडर
- * सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई — 1965 में
- * आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है — माउंट आबू में
- * एशियाई विकास बैंक का इंडिया रीजिडेंट मिशन अवस्थित है — नई दिल्ली में
- * राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में सही कथन हैं—
1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है।
 2. यह देश-भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है।
- * अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि — अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं।
- * सही सुमेल इस प्रकार हैं—
- | सूची-I
(वाद) | सूची-II
(विषय) |
|---------------------------------------|---|
| A. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य | निवारक अवरोध की प्रक्रिया |
| B. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य | स्वतंत्र भाषण पर रोक |
| C. शंकर प्रसाद बनाम भारतीय संघ | संविधान संशोधन की संसद की शक्ति |
| D. चम्पकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य | शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता |
- * सही कथन हैं—
1. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
 2. भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्य सभा द्वारा परित किए गए और लोक सभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है।
 3. वर्तमान में राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हैं।
- * सही कथन हैं—
- (a) संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।
 - (b) सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम पांच न्यायाधीशों द्वारा की जाती है।
 - (c) प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार-वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में सम्मिलित है।
- * 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकार्ड है — बिहार में
- * कथन (A): भारत में जातियों का राजनीतीकरण हो रहा है। कारण (R): भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। — दोनों (A) तथा (R) सत्य हैं, परंतु (R), (A) का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है।
- * 2003 में गोरखाओं को ओ.बी.सी. का दर्जा दिया गया — उत्तराखंड में
- * वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है — कार्ल मार्क्स को
- * जिलाधीश को 'संस्थागत करिश्मा' कहा था — रजनी कोठारी ने
- * राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां भेजी जानी आवश्यक हैं — मुख्य सचिव के माध्यम से
- * द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है—
- नोट — संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार, मानवाधिकार कहा गया है।
- * भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, वर्ष— — 2003 में
- * सही कथन हैं—
- (i) भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है।
 - (ii) बिच आरोग्य का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है।
 - (iii) 'पॉलिटिक्स इन इंडिया' रजनी कोठारी का पथप्रदर्शक शोध अध्ययन है।
- * विश्व का नवीनतम राष्ट्र है — दक्षिण सूडान
- * यू.एन. द्वारा सन् _____ को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। — 1975
- * भारतीय विदेश नीति, जो तटस्थता पर आधारित थी, को प्रारंभ किया था — जवाहरलाल नेहरू ने
- * यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम है — स्वीडन
- * अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है — 3 दिसंबर को